सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 नवम्बर, 2019

षोडश विधान सभा — बुधवार, तिथि 27 नवंबर, 2019 ई0

चतुर्दश सत्र — 06 अग्रहायण, 1941, (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में जंगल राज है ।

श्री ललित कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे कार्यों को रोककर कार्य-स्थगन मंजूर किया जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये और एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान जारी)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या : 07 (श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड-1 स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास का लाभ पाने हेतु छूटे हुये योग्य परिवारों का नाम आवास ऐप के माध्यम से शामिल करने हेतु विभागीय पत्रांक संख्या-370600 दिनांक 22.05.2018 द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिये गये हैं । उक्त निर्देश के आलोक में राज्य में कुल 32 लाख 86 हजार परिवारों का नाम आवास ऐप पर अपलोड किया गया है । भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक संख्या-एम.12018/02/2019/आर0एच0एम0एस0टी0 दिनांक 29.10.2019 से प्राप्त अद्यतन निर्देश के आलोक में राज्य स्तर पर प्रतीक्षा सूची में लाभुकों की संख्या समाप्त होने पर ही आवास ऐप के माध्यम से जोड़े गये नामों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जा सकता है ।

(व्यवधान जारी)

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री ने आवास के लिये तो एक स्थिति बताई है कि

प्रतीक्षा सूची समाप्त होने के बाद ही 32 लाख 86 हजार आवास के लिये ऐसे योग्य लाभुक हैं, जिनका नाम ए.सी.सी.एस. डाटा में नहीं है, उनको मिल सकता है लेकिन वैसे सभी लोगों को अन्य सुविधायें भी नहीं मिलती है । आवास के आलावे भी वे अन्य सुविधाओं से वंचित हैं । तो क्या सरकार अन्य सुविधाओं जैसे- राशन कार्ड की सुविधा और बाकी सुविधाओं के लिये फिर से कोई आर्थिक सर्वेक्षण कराकर भारत सरकार को भेजने का विचार रखती है ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न पर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार को हमलोग 32 लाख 86 हजार नाम भेज चुके हैं और पहले से जो सामाजिक, आर्थिक जनगणना, जो 2011 में हुये, उस सूची के अनुसार पूरे लोगों का जब घर बन जायेगा तब ये शुरू किया जायेगा । लेकिन महोदय, माननीय सदस्य एक दूसरा प्रश्न यह पूछ रहे हैं कि आवास की सुविधा मिल जाती है लेकिन अन्य सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं, महोदय, उनके बारे में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहार में एक योजना चलाई है, जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना । महोदय, सतत जीविकोपार्जन योजना में, जो परिवार किसी भी सरकारी लाभ से वंचित हैं, उसकी सूची बना रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं और महोदय, जीविका के माध्यम से सूची बन रही है, वैसे परिवार जो छूटे रहेंगे, उनको सतत जीविकोपार्जन योजना में शामिल करके उनको भी लाभ पहुंचाने का काम बिहार की सरकार करेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसमें मेरा केवल एक अनुरोध है कि अगर संभव हो तो एक सामाजिक, आर्थिक जनगणना राज्य सरकार कराकर भारत सरकार को एक अनुशंसा भेज दे ताकि राशन कार्ड जैसी सुविधाओं जो वंचित हैं, उनको उसकी सुविधा मिल सके ।

श्री श्रवण कुमार : हुजूर, हमने तो कराया है और तब 32 लाख 86 हजार लोग उसमें निकले हैं और भारत सरकार से माननीय सदस्य, चूंकि दिल्ली में सरकार है, वहां जाकर वहां से सुविधा प्रदान करायें तो बिहार के लोगों को जल्दी-जल्दी सुविधा मिल जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पूरे राज्य में जहां विधि-व्यवस्था ध्वस्त हो, वह प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमलोग कार्य-स्थगन दिये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप का प्रश्न डस्टबीन खरीदने से संबंधित है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बिहार में विधि-व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है ।

अध्यक्ष : क्या आपको प्रश्न नहीं पूछना है ?

(व्यवधान जारी)

जब आपको सवाल पूछना ही नहीं है तो सदन की कार्यवाही.....

माननीय सदस्यगण, आपलोग शांत रहियेगा तब न सुनियेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब शांत रहियेगा तो हम ......

(व्यवधान जारी)

सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/अंजनी/27.11.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम,2014 की कंडिका-10 के तहत "बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम,2019" की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम,2014 की कंडिका-10 के तहत "बिहार पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम,2019" की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी।

माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री श्याम बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का जल संसाधन विभाग से संबंधित 278वां एवं श्रम संसाधन विभाग से संबंधित 280वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

<u>वित्तीय-कार्य</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या-38 है, आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-21, शिक्षा विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन के द्वारा किया जायेगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है, विभिन्न दलों को उनकी संख्या के आधार पर समय का आवंटन किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	-	60 मिनट
जनता दल(यूनाइटेड)	-	51 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	40 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	19 मिनट

सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	01 मिनट
निर्दलीय	-	04 मिनट

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य अनुपूरक अनुदान मांग पर विमर्श ।

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"शिक्षा विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च,2020 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबंध के अतिरिक्त 16,10,04,71,000/-(सोलह अरब दस करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय"।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदेव यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की मांग संख्या-21 के संबंध में 31 मार्च,2020 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबंध के अतिरिक्त 16,10,04,71,000/-(सोलह अरब दस करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार) रूपये में से 10/-रूपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूँ और इस पर सदन में विमर्श हो ।

महोदय, शिक्षा विभाग की जो बदहाली है, उसपर मैं कहां से शुरू करूं और कहां अंत करूं, यह समझ में नहीं आता है । शिक्षा विभाग की जो बदहाली बिहार में है, उससे बिहार के शिक्षा विभाग का पूरे देश में जो बदनामी है, जो छात्र

यहां से डिग्री लेकर जाते हैं, जो छात्र यहां से बाहर पढ़ने जाते हैं । आज मैं असमंजस में हूँ कि शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करूं । महोदय, हम सरकार की उस शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करें, जहां बच्चे पेड़ के छाये के नीचे पढ़ते हैं । अभी-भी प्राथमिक विद्यालय, जो बुनियादी विद्यालय हैं, वहां बच्चे के पठन-पाठन के लिए कमरा नहीं है । सैकड़ों हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं और कहीं-कहीं छत के अन्दर और छत ऐसा है कि कब गिर जाय और दिवार जो है, उससे कीड़े, बिच्छु आदि निकलते हैं, जिसके कारण बच्चे संशय की स्थिति में रहते हैं, तो बिहार की यही शिक्षा व्यवस्था है महोदय । बिहार के कितने छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं और उनका कितना आर्थिक शोषण होता है, यह हम आप सभी जानते हैं । यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहती तो बिहार के लड़के बाहर नहीं जाते महोदय । महोदय, आप देख लीजिए कि बंगलोर से लेकर राजस्थान के कोटा एवं अनेक राज्य में कितने छात्र जाते हैं और इसका आंकड़ा सरकार के पास होगा । महोदय, सरकार आंकड़ा प्रस्तुत करे तो हम बिहार के लोग शर्मसार हो जायेंगे । सरकार आंकड़े प्रस्तुत करे कि बिहार से कितने छात्र बाहर पढ़ने के लिए पलायन करते हैं । जहां आपके पास प्राथमिक शिक्षक न हो, प्राथमिक विद्यालय के भवन न हो, जहां छतविहिन विद्यालय में बच्चे पढ़ते हों, पेड़ के नीचे पढ़ते हों, हम उस बिहार के शिक्षा व्यवस्था का क्या ब्याख्यान करें । हम बिहार के शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप सिर्फ आंकड़ा मंगा लीजिए कि बिहार से कितने छात्र प्रत्येक वर्ष पलायन करते हैं, कितने छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए, चाहे उच्च शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो । आज बिहार में सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है, वहीं आपके प्राइवेट विद्यालय की क्या स्थिति है, हम दोनों की तुलना करें तो पता चल जायेगा । हम सरकार से आग्रह करते हैं, शिक्षा के बिना, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में आप बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं ? आप जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कीजियेगा तबतक कुछ नहीं हो सकता है । आपने उच्च विद्यालय का निर्माण कराया है, इस बात को हम मानते हैं । आपने विद्यालय को उत्क्रमित कर दिये मध्य विद्यालय में लेकिन उस विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं। आप प्राइमरी या मिडिल स्कूल के शिक्षक से उच्च विद्यालय और 10+2 चला रहे हैं । एक भी विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, विषयवार शिक्षक की बात तो दूर रही । गणित, फिजिक्स और केमेस्ट्री की बात तो दूर रही, किसी भी विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं। विषयवार शिक्षक के संबंध में तो हम बाद में

आयेंगे । विषयवार शिक्षक तो स्कूल में है ही नहीं सिर्फ भवन बना देने से नहीं होगा । आपका एक शिक्षक नहीं है । आपने जिन विद्यालयों को उत्क्रमित किया है, उसका पता कर लीजिए, कहीं शिक्षक है, भवन है ? भवन जो बना, वह अब टूट रहा है, गिर रहा है । अभी तक आप शिक्षक की बहाली नहीं कर पाये हैं ।

श्री रवीन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं ।

अध्यक्ष : कितने दिनों के बाद तो सदन ब्यवस्थित रूप से चल रहा है, आप इस ब्यवस्थित सदन में क्या व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र यादव : महोदय, राजनीति में जो समाज सेवा में टॉप पर हैं, उनको भी शिक्षित होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी ही बात पर रहिए न, वे जो बोले, उसको आप भूल जाइए ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, रविन्द्र जी किस-किस विद्यालय के छात्र रहे हैं, वे अपने प्रिंसपल का नाम जानते होंगे ? हम इनके प्रिंसपल का नाम बताना नहीं चाहते हैं । ये भूल जाते हैं अपने प्रिंसपल का नाम, तो यह ध्यान में रखिए कि किस-किस कॉलेज से ये गये हैं और किस-किस प्रिंसपल के अन्डर पढ़े हैं । ये भूल जाते हैं नाम । महोदय, ये कभी इधर, कभी उधर करते रहते हैं, उसपर हम नहीं जाना चाहते हैं ।

टर्न-3/राजेश/27.11.19

श्री ललित कुमार यादव, क्रमशः ... महोदय, कभी इधर, कभी उधर करते रहते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं । महोदय, हम कह रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था, सरकार यदि बिहार में दुरुस्त करें महोदय तो बिहार का विकास संभव है........... (व्यवधान)

अध्यक्ष: आप उनके गुरु या प्रधानाचार्य का नाम बताना चाहते हैं क्या ?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हम शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करना चाहते हैं जो शिक्षा व्यवस्था हीन है । महोदय, हम उस शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करें जहॉ के शिक्षकों को अपनी उचित मांग के लिए दौड़ा-दौड़ाकर पिट-पिट कर मारा जाता हो और उनकी मांग नहीं सुनी जाती हो और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाती है, समान काम के समान वेतन की मांग करता हो, सेवा शर्त लागू करने की मांग करता हो, अपने पेंशन के लिए मांग करता हो, सरकार उसको दौड़ा-दौड़ाकर मारती है, तो उस सरकार से हम शिक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं महोदय, वह सरकार क्या उत्तम शिक्षा दे सकती है, जहॉ दोहरी मापदंड हो और जहॉ शिक्षक भूखे हों और शिक्षक को न्याय नहीं मिले,

तो हम छात्र को कहाॅं से न्याय देंगे महोदय यह शिक्षा जो बिहार का है, इसको आईने की तरह सरकार को लेना चाहिए, दूसरे राज्यों में भी सरकार ने शिक्षा पर जो ध्यान दिया है, बजट तो मेरा बढ़ता है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं होती है, केवल बजट में बढ़ोत्तरी होती है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट होती है, इस शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में जो विकास हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप बिहार में भी उसी पैटर्न पर शिक्षा व्यवस्था को कीजिये, तो हमारा बिहार निश्चित रुप से विकास करेगा, हमलोग विकसित बिहार देखना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि विकसित बिहार हो, हमलोग भी चाहते हैं कि विकसित बिहार हो, हम आपके साथ है, विकसित बिहार में कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है महोदय लेकिन अभी जो शिक्षा की व्यवस्था है.........

(व्यवधान)

महोदय, बजट तो बढ़ा है लेकिन शिक्षा की बदहाली बढ़ी है, यह मैं नहीं कह रहा हूॅं इनका जो सी0बी0जी0ए0, सेन्ट्रल ऑफ बजट गवर्नेंस एकाउन्टिबिलिटी का जो रिर्पोट है महोदय और कई संस्थाओं की रिर्पोट में यह खुलासा हुआ है महोदय कि प्राथमिक स्तर पर 39 प्रतिशत शिक्षक पेशेवर रुप से प्रशिक्षित नही है । महोदय 2015-16 से 2016-17 के बीच छात्रों को स्कूलों से छोड़ने वालों की संख्या में 9.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । महोदय, बिहार में दो लाख 78 हजार से अधिक शिक्षकों का पद खाली है, उसीतरह से 2014-15 से 2017-18 के बीच स्कूली शिक्षा पर खर्च 52 प्रतिशत बढ़ा, फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो रहा है बिहार में । महोदय, शिक्षक और छात्र के अनुपात में भारी कमी है । महोदय, राज्य के 4500 स्कूलों में पधार रहे है एक शिक्षक, तो हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बात कहाॅं से करेंगे, उसीतरह से राज्य के 2300 ग्रामीण स्कूलों में पधार रहे हैं एक-एक शिक्षक, राज्य के 1400 प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन स्कूल छात्रों की संख्या 40 से भी कम राज्य के 6 से 16 साल के बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षकों की सर्टिफिकेट जांच में 81 हजार से अधिक शिक्षकों के फोल्डर गायब है महोदय । महोदय, शिक्षकों के सर्टिफिकेट में 81 हजार शिक्षकों का फोल्डर गायब हैं, बिहार में 2019 तक 53 हजार सही आवेदनों में से मात्र 17 हजार छात्रों को मिला न्याय महोदय, तो इसतरह से शिक्षा विभाग और शिक्षा के बारे में क्या बखान किया जाय । महोदय, राज्य के 171 प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या राज्य में 20 से 30, नामांकन की संख्या 336, इसतरह से महोदय शिक्षा की बदहाल स्थिति है । अब हम अनुरोध करेंगे महोदय कि

मेरे पार्टी की ओर से जो नाम आपके सामने दिया गया है, हम चाहेंगे माननीय सदस्य नेमतुल्लाह जी को इजाजत दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष: अब तो अगले ही टर्न में न ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा ।

अध्यक्ष: मकसद क्या है ?

श्री भाई वीरेन्द्र: माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छे आदमी है ।

अध्यक्ष: यह बात आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र: और अगर ये अपने विवेक से काम करेंगे, तो शिक्षा में काफी सुधार आ जायेगा, लेकिन हर चीज में वे माननीय मुख्यमंत्री जी से राय लेते हैं,अगर इन्हें बाथरुम भी जाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो ये जाते हैं, तो ये छोड़ दें माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष: लेकिन शिक्षा मंत्री जी तो बता रहे थे कि जिसमें भाई वीरेन्द्र जी राय नहीं देते हैं, उसी में हम राय दूसरे से लेते हैं । माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा जी ।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, मैं आज शिक्षा विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, हमने माननीय सदस्य विपक्ष के मेरे भाई ललित जी ने जो विचार रखे हैं, हमको सुनकर हॅसी आ रहा है कि इनके रीजन में मनुष्य को पढ़ाने की बात नहीं होती थी बल्कि पशु के पढ़ाने की बात होती थी और इसी के तहत चरवाहा विद्यालय खोले गये थे, आज वह व्यक्ति शिक्षा की बात कर रहा है महोदय, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा विपक्ष के भाईयों से कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा के जगत में अलख जगाये हैं, वह पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका अनुकरण हो रहा है । आज पूरे बिहार के हर पंचायत में प्लस टू हाईस्कूल की व्यवस्था की गयी है, स्कूल में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, बच्ची को बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने साईकिल योजना की व्यवस्था की, साईकिल योजना पूरे बिहार में लागू हुआ, जिसका हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका अनुकरण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के क्रिया कलाप को । महोदय, इतना ही नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब छात्रों के लिए, लडकी के लिए उन्होंने पोशाक राशि की व्यवस्था की, जो पोशाक के चलते पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, उनको पोशााक की व्यवस्था की । महोदय, उस लड़की को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लड़का को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इन्होंने प्रोत्साहन राशि की

व्यवस्था की, मैट्रिक फस्ट डिवीजन से पास करने पर 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की, इन्टर पास करने पर 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की और इतना ही नहीं महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी का जो नीति और सिद्वांत है शिक्षा के जगत में, वह आज तक अनुकरणीय है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि दलित और महादलित के विकास के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन्होंने टोला स्वयंसेवक की बहाली की है, 40 हजार टोला स्वयंसेवक को बहाल करके गरीब दलित, महादलित के बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने टोला स्वयंसेवक का बहाली किया महोदय और इतना ही नहीं आज महिलाओं को साक्षर करने के लिए अक्षर आंचल योजना की व्यवस्था की महोदय और इनके समय में जो व्यवस्था थी, वह कहने लायक नहीं है महोदय और पूरे बिहार में जहॉ भी दो मंजिला भवन हो या तीन मंजिला भवन हो, वह नीतीश कुमार जी का देन है, जो प्लस टू चाहे वह मध्य विद्यालय हो, उसको उत्क्रमित करके इन्होने प्लस टू में परिवर्तित करने का काम किया है महोदय ।

(इस अवसर पर श्री मो0 नेमतुल्लाह ने सभापति महोदय का आसन ग्रहण किया)

टर्न-4/सत्येन्द्र/27-11-19

श्री रत्नेश सादा(क्रमशः) महोदय, आज हर क्षेत्र में जो विकास हो रहा है शिक्षा के जगत में, यह सराहनीय कदम है महोदय । आज शिक्षा नहीं होती, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है महोदय ये नीतीश कुमार का ही देन है । इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह):भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, 11 मिनट टाईम है आपका ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: जी, सभापति महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश द्वितीय अनुपूरक बजट पर माननीय सदस्य श्री ललित जी द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज यहां शिक्षा विभाग पर चर्चा चल रही है और माननीय सदस्य ललित जी बोल रहे थे कि गांव में कई ऐसे विद्यालय हैं जिसको अपना छत नहीं है लेकिन वह पहले का समय था, 1990 से 2005 का जो समय था महोदय, उस समय का जो चित्रण उनके दिमाग में था, उस समय का जो दृश्य उनके दिमाग में था, मुझको लगता है कि शायद वही दृश्य आज भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है । महोदय, आज शायद ही कोई विद्यालय ऐसा होगा जहां

विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए बेंच और बच्चों के सिर पर छत नहीं है। महोदय, आज शिक्षा में लगातार उत्तरोत्तर इस सरकार में प्रगति होते जा रहा है जिसे इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय विधायक ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं । महोदय, अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने जो उन्नयन बिहार कार्यक्रम चलाया है, शायद ही कोई इसमें बैठे हुए माननीय सदस्य होंगे जो अपने क्षेत्र के हाई स्कूलों में जाकर किसी न किसी स्मार्ट क्लास का उद्घाटन नहीं किये होंगे, दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि वह जो दिन था, जब चरवाहा विद्यालय, धोबी घाट विद्यालय हुआ करता था जो अब कहीं दिखलाई भी नहीं पड़ता है और आज वह समय है जब स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और आज विद्यालयों में जाकर हमारे माननीय सदस्य उसका उद्घाटन कर रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं । लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ यह बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में आज जब आंकड़े आई.ए.एस. के रिजल्ट निकलते हैं आई. पी.एस. के रिजल्ट निकलते हैं टॉप लेवल के जितने भी पढ़ाई के रिजल्ट निकलते हैं उसमें पता चलता है कि देश के पैमाने पर बिहार के बच्चे सबसे अव्वल कर रहे हैं और सबसे अधिक कम्प्टीशन कम्प्लीट कर के अच्छे और उच्च नौकरियों में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन का परिणाम है कि आज बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ सिर्फ बिहार को ही नहीं सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को नजर आ रहा है इसलिए मैं माननीय विपक्ष के साथियों से आदरणीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आपको देखना भी है निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि कहीं-कहीं कोई विद्यालय भूमिहीन भवनविहीन हो सकते हैं जिसमें हमारी भी पूर्ण भूमिका है अब जमीन के आवश्यकता होती है पहले समाज में जमीन लोग दान दिया करते थे गिफ्ट करते थे अगर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं जवाबदेही का निर्वहन करते हैं तो किसी को प्रेरित करते हैं तो आज भी ऐसे लोग समाज में मिल जाते हैं जो शिक्षा के लिए जमीन दान देते हैं और वहां जो भूमिहीन भवन रहते हैं वह भूमि के साथ भवन भी वहां निर्माण करने के लिए सरकार उसकी व्यवस्था करती है और सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है, लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, मैं कुछ तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें गुणात्मक सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। आज शिक्षक बन्धु जो शिक्षा का काम कर रहे हैं वे भी हमारे ही परिवार के लोग हैं वे भी हमारे

घर के सदस्य हैं और इधर आप देख रहे हैं कि कई दिन से उनका भी धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें बात चल रही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं और नियमित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक का दर्जा देने के लिए हमारे नियोजित शिक्षक बन्धु सड़कों पर नारे लगा रहे हैं और हम लोगों के यहां आकर मैं समझता हूँ कि दो-तीन दिन पहले शायद ही कोई विधायक माननीय सदस्य होंगे जिनके दरवाजे पर जिनके डेरा पर कुछ न कुछ उनके क्षेत्र के शिक्षक आकर ज्ञापन नहीं दिये होंगे इसलिए मैं वरीय पदाधिकारी बन्धुओं से और मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इसको देखिये मैं समझता हूँ कि कुछ वैधानिक कठिनाईयां हो सकती हैं, संवैधानिक प्रॉब्लम हो सकती हैं कोर्ट का कोई जूरिडिक्शन हो सकता है, लेकिन आपको इस बात पर चिन्तन करना चाहिए कि जो शिक्षक लगातार काम कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से समान काम के बदले समान वेतनमान देने पर विचार करना चाहिए मैं दूसरा एक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिन नियोजित शिक्षकों का नियोजन 2004 में हुआ और जिनका 2016 में हुआ आपने जो उसमें नियम बनाये हैं उसमें जरा संशोधन करना होगा जिन्होंने 2004 में नियोजित हुए जो शिक्षक बहाल हुए आप 2004 वाले को 2016 वाले का वेतनमान एक रूप में रखे हैं इसलिए उनको सिनियरिटी के आधार पर तय करना चाहिए कि जो शिक्षक सिनियर हैं उनको सिनियरिटी का दर्जा मिलना चाहिए और शिक्षक बाद में बाहल में हुए हैं फिर क्रमानुसार उनको प्रमोशन देना चाहिए उनका जो वेतन हैं भत्ते हैं उसमें उनका संशोधन करना चाहिए इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ और सुझाव भी दे रहा हूँ सरकार को कि सरकार को इसे नोट करना चाहिए, पदाधिकारी को इस पर अमल करना चाहिए और इसमें संशोधन जरूरी है तो उसको देखना चाहिए और ठीक उसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी बिहार की सरकार लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है मैं महोदय कहना चाहता हूँ पं0 दीन दयाल योजना जो बिजली के क्षेत्र में लागू है जितने माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जा रहे हैं गांव के गरीब लोग भी जो दिवाली के समय में लाल पीली बत्ती अपने घरों पर लगाये हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक आंधी आकर उनके बत्तियों को उखाड़ेगी नहीं तब तक उनके घरों पर लाल पीली बत्ती जलती रहेगी और गांव में उजाला फैला हुआ है जब हम न्योता निमंत्रण में गांव में जाते हैं। तो कभी कभी उस चकाचौंध में भूल जाते हैं कि किसके दरवाजे पर हमको जाना है चूंकि कई दरवाजे पर बड़ा-बड़ा वैपर जलता रहता है कभी एक जमाना था जब डिबरी की रोशनी दिखलाई पड़ती थी दूर से लालटेन की रोशनी दिखलाई पड़ती थी तो लगता

था कि कोई गांव है कोई घर है लेकिन आज सारे माननीय सदस्य इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि हर गांव में बिजली हर घर में बिजली और उस बिजली का मजा इस प्रकार से हमारे गांव के गरीब ले रहे हैं वे गर्मी के दिन में अपना कपड़े को पंखा चलाकर सुखा रहे हैं । बाहर कपड़ा सुखाते हैं तो उनको लगता है कि उसका रंग उड़ जायेगा इसको ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हैं और इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1990 से लेकर 2005 तक आपने जितने इन्दिरा आवास के पैसे बांटे गांव के गरीबों के बीच में सरकार उसका एक तरह से पैमाईश करा ले कि उसमें से कितने गरीब घर बनाये लेकिन आज प्रधान मंत्री आवास योजना से जो पैसा हमारे गरीबों को दिया जा रहा है गांव में दिया जा रहा है उसकी प्रगति को आप देखेंगे कि आज वही गरीब को जो प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिल रहा है आज उससे घर बन रहा है । आप किसानों की स्थिति देख लीजिये कोई भी माननीय सदस्य अपने गांव का अपने क्षेत्र का सर्वे करा लें, कोई भी माननीय सदस्य जब सर्वे करायेंगे तो पायेंगे कि उनको किसी एक गांव का अगर सर्वे कराते हैं तो उस गांव में एक एकड़ से कम जमीन जोतने वाले की संख्या है 90 प्रतिशत आज के दिनों में और वैसे सभी परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6-6 हजार रु0 उनके खाते में जा रहा है । जिनके लिए कोई पैरवी नहीं करना पड़ रहा है पैसा जा रहा है 2-2 हजार रु0 कर के जा रहे हैं फिर किसान सम्मान पेंशन योजना 60 साल के बाद किसान एक ऐसी जाति है किसान एक ऐसी व्यवस्था है उनके पास पेंशन के नाम पर कुछ नहीं है हमें भी पेंशन मिलेगा सरकारी पदाधिकारियों को भी पेंशन मिलेगा अन्य लोगों को भी पेंशन मिलेगा लेकिन गांव के गरीब किसान जिनके लिए पहली बार किसी ने चिन्ता किया कि उन किसानों को भी पेंशन मिलना चाहिए जब वे रिटायर होते हैं जब वे बूढ़े हो जाते हैं परिवार में जब आमदनी का कोई निश्चित सोर्स नहीं रहता है तो उनकी क्या स्थिति होती है कि वे किसान खैनी चूना खाने के लिए तरसते रहते हैं लेकिन भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने इसकी व्यवस्था की है कि किसानों के 6 हजार रु0 को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा और जब वे थोड़ा-थोड़ा भी पैसा जमा करा देंगे तो 60 साल के बाद उनको 3 हजार रु0 का पेंशन मिलेगा इसके लिए पहली बार किसी ने चिन्ता किया है हमारी सरकार ने चिन्ता किया है कि 70 साल तक जो सड़कों पर अपने घर परिवार के लोगो को नंगा देखते थे नग्न शरीर देखकर उनको लज्जा आ जाती थी आज वैसे 98 प्रतिशत लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं । हमारी बीवी बहनों की इज्जत की रक्षा हो रही है । पहली बार

इस सरकार ने चिन्ता किया है इसके पहले इस देश में किसी सरकार ने इसकी चिन्ता नहीं किया । आज बिहार और पूरा भारत प्रगति के रास्ते पर जा रहा है तो कुछ लोगों को लग रहा है कि जो पहले प्राप्त होता था लड्डू उसका दिन चला गया । अब वह दिन कैसे आयेगा उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और उसी व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था पहले चलती थी उसी में उनका दिमाग लगा रहता है । (क्रमशः)

...क्रमशः..

टर्न-5/आजाद/27.11.2019

..... क्रमशः ......

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, समय कम है, मैं पुनः आग्रह करता हूँ, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, समय समाप्त हो रहा है, मुझको बैठना पड़ेगा, इस निवेदन के साथ कि शिक्षक बंधुओं की, शिक्षण संस्थानों में जो कमियां हैं, टीचर्स की बहाली करने की जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, पदाधिकारियों से या माननीय मंत्रियों से जो बात होती है, वे कहते हैं कि प्रक्रियाधीन है, विनम्र प्रार्थना होगा, विनती होगी, रिक्वेस्ट होगा कि आप टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया को सरल बनाईए और जल्दी से जल्दी हाईस्कूल में शिक्षक भेजीए ताकि विद्यालयों में जो पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है और वह बेहतर होगी । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद । पूरे बिहार के लोगों को नमस्कार करते हुए सदन की प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपने समय सीमा में अपनी बात समाप्त किया, बहुत,बहुत आपको धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह । आपका 14 मिनट समय है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग का जो मांग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और माननीय सदस्य विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, विपक्ष का काम होता है कटौती प्रस्ताव लाना और सरकार को सही सुझाव देना और सरकार का काम होता है उन सुझावों पर ध्यान देकर जो सही है, उसको लागू कराना । लेकिन आज उल्टा हो गया है । आज हम अभी बताने जा रहे हैं तब तक संसदीय मंत्री जी का चिलचिलाहट शुरू हो गया है । सभापति महोदय, श्री ललित बाबू ने बहुत स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग जो विभाग है, जिसके बारे में सारे लोग श्रेय ले रहे हैं, उसके बारे में श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को बिहार

में जायेगा तो उस व्यक्ति का नाम है श्री नीतीश कुमार जी, जो इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं । मगर दूसरा श्रेय जायेगा यू0पी0ए0 गवर्नमेंट को, जो सर्वशिक्षा अभियान को, बिहार में लाकर के बिहार में सर्वशिक्षा अभियान लाकर के शिक्षा में सुधार लाने का काम किया । मगर सभापति महोदय, ललित बाबू ने जो कहा, आज भी यह बात सही है कि हमारे गया में वजीरगंज प्रखंड में आज भी वैसे विद्यालय गांव में हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं । दलितों का गांव, पिछड़ों का गांव, गरीबों का गांव है, जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं । उदाहरण के रूप में हम आपको दो नाम बता देता हूँ, एक फतेहपुर जो सकदा नवादा में है और नोनडीहा खुद जो है, यह दो गांव कुकराह पंचायत में हैं, आप इसकी जॉच करा लें । बच्चे आज भी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, यह मैं आपको दे रहा हूँ । वजीरगंज प्रखंड के मोहाईन पंचायत के लालू प्राथमिक विद्यालय और मानपुर प्रखंड के सादीपुर पंचायत जहां पर संसदीय मंत्री जी गये हैं और वहां पर भोजन भी किये हैं और वहां का मध्य विद्यालय, यह दो जगह आज भी भवनविहिन स्कूल है । हमने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सूची दिया है, जिसमें वजीरगंज विधान सभा क्षेत्र में 28-29 ऐसे विद्यालय हैं, जो आबादी कम्पीट कर रहा है और वह दलित और पिछड़ा गांव है और वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है और विभाग के कान पर इसके लिए जूं नहीं रेंग रहा है । आज हम आपको बता रहे हैं और शिक्षा की बात किया जा रहा है, सकरदास, नवादा में हाईस्कूल आज का नहीं है, वहां का सकरदास नवादा के बच्चे पढ़ने वाले भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हुआ और आज उस सकरदास नवादा में शिक्षा विभाग भेज देता है प्रयोगशाला के लिए सामान और उसको रखने के लिए भवन नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री जी, हाईवे पर है और आज वहां विद्यालय भवनविहिन है। किसको बताया जाय, शिक्षा विभाग के पास पूरा सिस्टम है और ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम है । सिर्फ प्रधान सचिव का काम नहीं है, सिर्फ शिक्षा मंत्री का काम नहीं है । आर0डी0डी0, डी0ई0ओ0 जो सरकार के तरफ से वेतन ले रहा है, मगर कभी उन लोगों ने इसके बारे में अनुशंसा किया है क्या कि सकरदास नवादा में जो हाईस्कूल हैं, वहां पर भवन नहीं है । 10प्लस टू तो कर दिया लेकिन वहां पर भवन कहां है ? शिक्षक कहां हैं, आज भी गांव में ऐसे स्कूल हैं, जिसमें शिक्षक नहीं हैं । सकरदास नवादा मध्य विद्यालय जहां प्रभारी हेडमास्टर है और एक शिक्षक हैं और लड़कों की संख्या वहां पर 400 से ऊपर है । जो सच्चाई है उसका अध्ययन करना चाहिए लेकिन उस पर अध्ययन नहीं हो पा रहा है । माननीय सभापति महोदय, आज

वजीरगंज में जो स्कूलें हैं, मैं आज भी सरकार को कह रहा हूँ, प्रधान सचिव बैठे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हमारे जिले से आते हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूँ, सूची मेरा विभाग में दिया हुआ है, उसकी जॉच करवा लें और सर्वशिक्षा अभियान के तहत उन गांवों में आप प्राथमिक विद्यालय खोलवाने की कार्रवाई करें । यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है । एक ही चीज रिपीटेड होता है सत्ता पक्ष की ओर से, साईकिल मिल गया, वस्त्र मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया लेकिन बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, शिक्षक गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे हैं या नहीं ? माननीय नगर विकास मंत्री जी, कृपया आप बैठिए । आपको मैं बताता हूँ, यह स्थिति है शिक्षा का । समय का अभाव है, मैं एक प्वायंट पर नगर विकास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । जल, जीवन और हरियाली पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच हो रहा था, संसदीय मंत्री जी भी वहां पर थे और वहां पर माननीय मंत्री लोग बैठे थे । उसमें जितना वो ध्यान दे रहे थे, जितना फोकस दे रहे थे, उसको हम टी0वी0 पर देखे थे.....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, इतना सिनियर मोस्ट लिडर हैं, या तो इनके ऑख में कमजोरी है या यादाश्त में कमजोरी है, मैं तो वहां पर गया ही नहीं था सभापति महोदय और मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि वहां पर बैठे थे ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : हो सकता है कि जो आर0ई0ओ0 मिनिस्टर हैं, उनसे आपका चेहरा मिल रहा था तो हमको लगा कि लाल बंडी आप पहने हैं भगवा वाला तो वही होंगे श्रवण कुमार । सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूँ, एक बार हमारे यहां नगर विकास मंत्री जी गये थे गया, हम उनको दिखाये कि गया मानपुर में 7 वार्ड है और वह नगर निगम से अपेक्षा करता है लेकिन यह 7 वार्ड उपेक्षित रहता है । माननीय मंत्री जी को ले जाकर के एक ड्रेन दिखाये, जैसे यहां पटना में राजीवनगर में ड्रैनेज बना रहता है नीचे नाला और ऊपर में रोड, हम मानपुरवासी जितने भी मानपुर जाने वाले लोग हैं, वे सभी लोग उस जाम में फंसते हैं । उसके लिए नगर विकास मंत्री जी ने आदेश दिया, बुडको द्वारा स्टीमेट बनाया गया, डी0पी0आर0 बनाया गया और वह डी0पी0आर0 गया नगर निगम में गया और नगर निगम ने उस डी0पी0आर0 को एप्रुव करके बुडको भेजा, बुडको उसको एप्रुव करके विभाग को भेजा और विभाग के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया दिनांक 30.09.2019 को और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पईन की गंभीरता को देखते हुए हमारे पत्र का जवाब 25.10.2019 को भेजा और 25.10.2019 को भेजने के बाद वह विभाग को भेज दिये और विभाग ने एक पत्र दिया है दिनांक 14.11.2019 को, जिसमें विभाग ने कहा है

कि इस योजना को मैं नगर निगम में भेज दिया हूँ । भाई कम से कम जो माननीय सदस्य का पत्र लिखा हुआ है, अगर आप उसी पत्र को पढ़ लेते तो नगर निगम में उसको भेजने की जरूरत नहीं थी, चूंकि इसकी फॅारमिलीटीज पहले ही पूरी हो चुकी है । इसका डी0पी0आर0 बन चुका है, बुडको ने अपना अनुशंसा कर दिया, नगर निगम ने अपना अनुशंसा कर दिया और आप हमको नगर विकास विभाग के सरकार के जो अवर सचिव हैं सेवक जी, सेवक जी सरकार का सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉरमिलीटीज कर रहे हैं । महोदय, इस पत्र को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ इसपर ध्यान दिया जाय और इस तरह से पदाधिकारियों द्वारा इसका माखौल नहीं उड़ाया जाय । नगर विकास विभाग के ऊपर के पदाधिकारी और बुडको का सी0एम0डी0 आई0ए0एस0 होता है, उसने अनुशंसा किया, नगर निगम का प्रशासक अनुशंसा किया, वार्ड पार्षद अनुशंसा किया और इसके बाद आप इसको कह रहे हैं कि नगर निगम को भेज दिया । क्या स्थिति है सभापति महोदय, इसलिए हम कहेंगे महोदय कि इस पत्र को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बनाकर नगर विकास विभाग से पूछा जाय। सभापति महोदय......

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि ये 2015 वाला चिट्ठी पढ़ रहे हैं या 2016 वाला, किस साल वाला चिट्ठी पढ़ रहे हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : देख लेंगे उसको ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, 2019 का है । उनके पेट में, हमने तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पत्र का संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग को लिखा और नगर विकास विभाग इसको नहीं करके नगर निगम को भेज रहा है जबकि माननीय मंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, वे बैठ गये हैं, हम उनको थैंक्स करेंगे, यह योजना उनका देखा हुआ है श्रवण बाबू,

.... क्रमशः .....

टर्न-6/शंभु/27.11.19

श्री अवधेश कुमार सिंह : क्रमशः..आप मानपुर से परिचित हैं, चूंकि आपका घर भी हमलोगों के अगल-बगल सटा हुआ है । जब मानपुर में आप मंत्री होकर के जाते हैं तो कितना समय लगता है पार करने में- अगर यह योजना बन गयी खजाहापुर सलेमपुर पैइन परियोजना पर है नाला और अगर यह नाला बन गया तो गांव के किसान, गंगटी, शेखाबीघा, शादीपुर, सोनी के किसान को जल भी मिलेगा, जो जल जीवन और

हरियाली जो मुख्यमंत्री का सपना है वह सपना इस योजना से पूरा होगा । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ हम कुछ अपने.....

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अभी आपका समय है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अभी माननीय विधायक बिजली के बारे में बड़ा बढ़िया से अटल योजना या कौन सा बोले हैं, वे लोग दिये हैं, जब यू0पी0ए0 गवर्नमेंट थी तो राजीव गांधी विद्युतीकरण इस बिहार में भी आया और उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर नजर आया उसी राजीव गांधी विद्युतीकरण का आप अनुशरण कर रहे हैं सिर्फ नाम बदल देने से आपको श्रेय मिलनेवाला नहीं है । यह काम अगर ईमानदारी से बोलें- हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री से कि राजीव गांधी विद्युतीकरण में खड़गपुर में काम हुआ था या नहीं हुआ था । यह सिर्फ ढकोसला करने से मेरे भाई काम नहीं चलेगा । राजीव गांधी विद्युतीकरण इस राज्य में आया और उसी में सारी एजेंसियां बिहार आई और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देंगे, इस आदमी को जो पढ़े लिखे सोच के आदमी हैं उस सोच को कार्यान्वित किये । आज शिक्षा में चाहे पक्ष हो या विपक्ष के लोग हों हमारे बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं, पार्ट वन पास कर रहे हैं, पार्ट थ्री पास कर रहे हैं और एडमिशन के लिए लाखों बच्चे आज भी रोड पर घूम रहे हैं । आप पता कर लीजिए कि उन बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है और लाइन मांगा जाता है और लाइन के बाद वे बच्चे कहां जायेंगे ? आपने कॉलेज तो बंद करा दिया उसके लिए हमको कॉलेज से न लेना है, न देना है, मगर उन बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है जो बच्चे वंचित हो रहे हैं उसपर भी कभी आपका ध्यान गया है, सरकार का ध्यान गया है ? इसपर ध्यान देना होगा, अगर इसपर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर वह कार्य होगा । दूसरी बात नियोजित शिक्षक की बात हुई थी सही बात है, चाहे पक्ष के मेंबर हों या विपक्ष के सभी जगह पर नियोजित शिक्षक गये । नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, जो होने लायक है उसको शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके एनाउन्स करें । सारे सदस्यों के घर पर रोज शिक्षक आ रहे हैं । शिक्षकों का कहना है कि आप हमारे मांग को नहीं बोले हैं, हमलोग बोलते-बोलते थक गये हैं, सारे विपक्ष के लोग थक गये मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है । सभापति महोदय, इसलिए आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उन शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें जो असमानता दूर करने की बात है जो 2004 में बहाल हुए हैं और 2016 में बहाल हुए हैं उसकी गुणवत्ता वगैरह को देख लें और उन शिक्षकों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, उनकी

मांग जायज है । इसी बिहार में 1980 में सरकार बनी थी उस समय शिक्षकों का वेतन क्या था, मगर एक कलम से बिहार सरकार ने निर्णय लिया और तमाम बिहार के शिक्षकों को चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे मध्य विद्यालय हो, हाईस्कूल हो या कॉलेज के शिक्षक हों सभी का समान वेतन बढ़ाने का काम किया । आज वही चीज आपको अपनाने का काम करना होगा और बिहार में शिक्षकों की बदहाली को दूर करना होगा । आज जिस मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं- चार साल बीत गया और चार साल से आप शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, मगर आज तक बहाली नहीं हुई । आज भी मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं । हम अनुरोध करेंगे इस सरकार से कि यथाशीघ्र वहां बहाली कराकर उन प्राथमिक विद्यालयों में, उन मध्य विद्यालयों में आप शिक्षक की नियुक्ति करें । इसी के साथ सभापति महोदय, हम तमाम अपने विपक्ष की ओर से जो सरकार को सुझाव दिये हैं उसपर सरकार से निवेदन करेंगे कि उसका अध्ययन करे और उसपर अमल करे । जय हिन्द, यह भारत ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : बहुत-बहुत धन्यवाद । अब राष्ट्रीय जनता दल के डा0 रामानुज प्रसाद जी ।

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, आज द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : 12 मिनट टाइम है, रामानुज जी ।

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, यह सरकार हमेशा अपने बेहतर प्रबंधन की बात, प्रचार और ढिंढोरा पीटती है । हमें पता नहीं चलता कि इसे क्यों बार-बार अनुपूरक बजट लाने पड़ते हैं, कुछ तो हैं जो आकस्मिक खर्च बढ़ जाते हैं वह तो ठीक लगता है, एप्रोप्रियेट लगता है, लेकिन हम जब इस पुस्तिका को पढ़ रहे थे तो कई ऐसे खंड सामने आये जिसमें इस्टेब्लीशमेंट ऐंट कमिटेड एक्सपेंडीचर पर भी सरकार के जो आये हैं उसको हमने देखा तो पता चलता है कि सरकार की जो कमिटेड एक्सपेंडीचर है उसमें भी सरकार को सप्लीमेंट्री बजट लेकर आना पड़ता है तो कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन माना जाय ? यह हम कहना चाहते हैं । जहां तक सवाल है सही है कि सरकार चर्चा करा रही है शिक्षा पर और इसपर ही कन्सन्ट्रेट करके बोलना है, लेकिन अभी राज्य और राज्य का मुख्यालय जिस तरह से बदहाल रहा, जिस तरह से कंकड़बाग के लोग हों, राजेन्द्र नगर के लोग हों, पूरे पटना के लोग हों, पूरे बिहार के हम जहां से विधायक होकर आते हैं, हमलोग दिनरात जल निकासी के लिए बेचैन होते रहे- मैं तो समझ रहा था कि इसी

विभाग आपदा को ही मुख्य मुद्दा बनाकर के आज बहस करानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा भी आवश्यक है । यह अगर शिक्षा पर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि साहब शिक्षा और स्वास्थ्य दो जो है किसी भी राज्य, राष्ट्र और मानव के विकास के महत्वपूर्ण कारक हुआ करते हैं और वे सामाजिक और आर्थिक संतुलन को बनाने का सबसे बेहतर विपन होता है कि अगर हम चाहते हैं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर सोशल इंजीनियर कहलाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग तो करते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा । वैसे हमारे साथी लोग कह रहे थे कि शिक्षा इन लोगों का सुधरा हुआ लगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा में सुधार की बात है । कहीं से भी हम चलें और शिक्षा पर चर्चा करें, स्वास्थ्य और अन्य विभाग को हम छोड़ दें तो कोई भी ये मान्य सिद्धांत है कि किसी भी सोसायटी का, किसी भी नेशन का, किसी भी स्टेट का रिफोर्म तभी होगा जब उसका ग्रासरूट का जो कौज हुआ करता है प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का हाल देखिए बिहार में तो मैं उन दिनों से देख रहा था जब एक सूची का मामला हुआ करता था । क्रमशः

टर्न-7/ज्योति/27-11-2019

क्रमशः

डा0 रामानुज प्रसाद : जब शिक्षा एक सूची का मामला हुआ करता था । राज्य का सिर्फ जब यह मामला था तब बदहाल हुआ करता था तब तो लगता था कि लौजिकल है। राज्य के जो संसाधन हैं, जो रिर्सोसेज हैं, उसपर हम जो काम करते हैं, हम लक्ष्य फुलफिल नहीं कर पाते हैं लेकिन इसको समवर्ती सूची में हमने अपने कंस्टीच्युशन में अमेंड करके 1976 में ही इसको समवर्ती सूची में डाला और समवर्ती में डाला इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ कि शिक्षा जो महत्वपूर्ण कारक और कारण है किसी भी राज्य या राष्ट्र के विकास के लिए, सोशल रिफौर्म के लिए, जो सोशल कौज है, सोशल जस्टिस का जो कौज है, उस कौज पर अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमको शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाना होगा लेकिन हम कहीं से नहीं पाते और एक चीज कह रहे थे हमारे भाई लोग, हम ज्यादा नहीं जायेंगे लेकिन एक चीज मुख्यमंत्री जी के भाषण को उद्धृत करते हुए कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में अपनी बात को रखते हुए और एक चर्चा करी थी । मुख्यमंत्री जी ने चर्चा के क्रम में कहा था, उन्होंने उद्धृत किया था कि ब्रिटेन के एक जर्नलिस्ट है टॉनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 2014 में लिखा था एक

पुस्तक इंडिया के कंटेक्सट में, उसमें मोदी इफेक्ट की चर्चा उन्होंने करी थी लेकिन उस मोदी इफेक्ट को कोट करते हुए और मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोदी इफैक्ट ता ेकितना दिखा, यह तो हो रहा है, फिर टॉनी ब्लेयर जी ने लिखा, उसी को मुख्यमंत्री जी ने फिर 2016 में चर्चा की थी टॉनी ब्लेयर ने लिखा कि साहेब मोदी इफेक्ट अब मोदी डिफेक्ट्स साबित हो रहा है तो मोदी के कारनामे आज जो देश में हो रहे हैं वह एजूकेशन के कंटेक्सट में भी मैं यहॉ रखना चाहूॅगा । सभापति महोदय, यह विदित सत्य है कि शिक्षा पर जो हमलोगों के दुनिया की जो सोच है, उस सोच के हिसाब से ही हम अगर समाज को अपने बिहार को बनाना चाहते हैं तो हमको इसपर काम करना होगा कि हम सोशल चेंज में, सोशल इंजीनिरयरिंग अगर करते हैं तो हम अगर काम करना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि ‘‘ If we want contribute to cause of social justice and work for betterment of the marginalized section of the society we should try our best to do better in education context" ये भी एक इशटैबलिश्ड प्रिंसपुल है और इस प्रिंसपुल पर अगर यह है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूॅ, मोदी इफेक्ट कितना बोले थे वह, यहॉ इतना समय नहीं है, 12 मिनट कह रहे हैं, अगर हमारी पार्टी समय देगा तो मैं बताऊंगा लेकिन मोदी इफेक्ट पर मैं आ रहा हूॅ कि मोदी इफेक्ट यह है शिक्षा के संदर्भ में कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था जो हमारे एक भाई कह रहें थे यू.पी.ए. सरकार की देन है सर्व शिक्षा अभियान का जो कौन्सेप्न्ट है लेकिन इस कौन्सेप्न्ट को जिसतरह से सारे विभागों के नाम बदले जा रहे हैं जैसे सारे संवैधानिक संस्थाओं को शैक्षणिक संस्थाओं को नष्ट ध्वस्त करने का और आर. एस.एस. के एजेन्डा को फिट करने की जो साजिश हो रही है, उसीतरह से सोशल जस्टिस प्रोग्राम के खिलाफ सर्व शिक्षा अभियान में जब कटौती की गयी, इसका नाम बदल दिया गया । नाम जिसतरह से योजना आयोग का बदल कर हमने कर दी है वह नीति आयोग । उसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान के नाम बदल करके इसको कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान लेकिन जब हमलोग बात करते हैं अपने डी.पी.ओ. से, जब बात करते हैं डी.ई.ओ. से, हम बात करते हैं डी.एम. से कि हमारे विद्यालय नहीं बन रहे हैं, हमारे विद्यालय बाढ़ में गिर गए हैं, ये भवन जर्जर है आप विद्यालयों को मर्ज कर रहे हो । भवन के अभाव में सारे मेम्बर्स बैठे हैं सभी हमारे मित्र बैठे हैं, आप बतायें किनके क्षेत्र में नहीं हो रहा है, सरकार आज जो बात कर रही है वह आप देखें । कुछ साथी कह रहे थे बेहतर मैं कहता हूॅ कि यह सरकार अगर जानी जायेगी

किसी चीज के लिए, एक चीज के लिए जानी जायेगी कि बिहार में शिक्षा को बदहाल करने के लिए, बिहार में शिक्षा को बदनाम करने के लिए, बिहार में शिक्षा को चौपट करने के लिए नीतीश जी जाने जायेंगे, नीतीश जी का इतिहास – माननीय मंत्री जी हंसिये नहीं जब आप आंकड़े देखेंगे । यह बड़ा गंभीर मसला है । सोशल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं लेकिन आप समाज नहीं बना सकतें हैं जबतक आप शिक्षा नहीं सुधारते हैं । जब तक आपका प्रायमरी एजूकेशन से लेकर के आपका सेकेंडी और हायर एजूकेशन किसी कौन्टेक्सट में बात कर लीजिये लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस हमें यह लगता है, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैसे आ गए मोदी इफेक्ट में ? आपने तो कहा था 2016 में कि मोदी इफेक्ट मोदी डिफेक्ट बन गया लेकिन फिर आप मोदी इफेक्ट में आ गये । जे.एन.यू. में हमारे लोग मार खा रहे हैं । गरीब के बच्चे मार खा रहे हैं । आप मुंह तक नहीं खोल रहे हैं । बी.एच.यू. में मारे जा रहे हैं बी.एच.यू. में कह रहा है कि कोई मायनरिटी का व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ायेगा, इसकी बहाली क्यों हो गयी ? इसतरह के भेदभाव हो रहे हैं इस देश में और आप शिक्षा के संदर्भ में बोल रहे हैं और आप मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी आप बैठे हुए हैं आप मुंह तक नहीं खोला और आप कह रहे हें कि शिक्षित करने आए हैं बिहार को, बिहार के गरीबों को आप गरीबों का वोट तो ले सकते हें लेकिन आप सोशल चेंज के कंटेक्सट में काम नहीं कर सकते हैं । सोशल जस्टिस आपका प्रोग्राम नहीं है । न्याय के साथ विकास बोलते हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास बोलिए नीतीश जी तब ही कुछ हो पायेगा, तब ही कुछ हो पायेगा । यह हमारा कहना है । सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखूंगा । हमारे क्षेत्र की समस्या में मैं राज्य की समस्या और देश की समस्या पर चर्चा के साथ अपने क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में एक तो शिक्षक साथियों ने हमें भार दिया है कि साहेब जो समान वेतन और समान काम , समान वेतन की मांग जिसका हमारी पार्टी और हमलोग और मैं व्यक्तिगत तौर पर समर्थन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, उसपर गौर फारमाने का काम करिये और कुछ ऐसा करिये मैं शिक्षक के हित में नहीं, मैं शिक्षा के हित में चाहता हुँ कि आप क्वालिटी एजूकेशन प्रोवाईड करने के तहत, क्वालिटी एजूकेशन कंटेक्सट को सुधारने के तहत आप इसको अवश्य करिये कि हमारा जो शिक्षक हो, वह डी.एल.एल. हो, बी.एड. हो जो भी हो वह एक कुशल शिक्षक हमारे लोगों को मिले हमारा गांव बदहाल है । हमारे गांव के विद्यालय बदहाल हैं । आप जमीन के अभाव में मर्ज कर रहे थे स्कूलों को, आपने भवन के अभाव में भी

करना शुरु कर दिया । हमने अपने डी.ओ. से कहा हमने अपने डी.पी.ओ. से कहा हमने अपने डी.एम. से कहा और बातें ये छन कर आती हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में पैसे नहीं है । पैसे की कटौती हो गयी । बी.आर.जी.एफ. कट गया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए राशि नहीं है । जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी सुन रहे हैं हम कहना चाहते हैं कि हम अपने विधान सभा में माननीय सभापति महोदय, मैंने विधान सभा में तीन बार सवाल लाए घुमा घुमा करके कभी तारांकित के माध्यम से, कभी निवेदन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से एक विद्यालय जो परकौलिया है जो पुरुषोत्तम बिशुनपुर है, सरकार का जवाब है कि हम उसको कर रहे हें और वह बाढ़ में ढह गया, उस विद्यालय के बच्चे अन्यत्र जा कर धूप में बरसात में, वह पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए अभिशप्त हो रहे हैं लेकिन यह सरकार ये सारन जिला के सोनपुर के दिघवारा प्रखंड के ये दोनों मामले दिघवारा प्रखंड के पुरईंया पंचायत के पुरुषोत्तम बिशुनपुर का मामला है । एक परकौलिया हजराजी पांचायत का मामला है और हमने देखा कि कहीं नहीं हैं । सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के 16 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक शिक्षक नहीं है । पदाधिकारीगण भी सुन रहे होंगे, यह पंचायत का नाम है सोनपुर प्रखंड है पंचायत है, चतुरपुर परमानंद पुर दुधैला, भरपुरा, नजरमीरा गंगा जल, सबल पुर पूर्वी, सबलपुर पूर्वी, सबलपुर पूर्वी, सबलपुर उत्तरी, शिकारपुर सोनपुर, सोनपुर, सोनपुर ये सारे हमारे जो विद्यालय है, यह पहाड़ीचक उर्दू विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय परवेजाबाद, प्राथमिक विद्यालय, मानपुर, प्राथमिक विद्यालय राजपुर टोला दरियापुर , प्राथमिक विद्यालय बिंदटोली, सबलपुर, प्राथमिक विद्यालय, हस्तीटोला, नौरसिया प्राथमिक विद्यालय, सहबाईज सबलपुर ये सारे ऐसे विद्यालय हैं जहॉ एक भी शिक्षक नहीं है । हमलोग जाते हैं लोगों की जलालत और लोगों की बात सुनते हैं और जब सामाजिक न्याय पर बोलते हैं तो गरीब लोग कहतें हैं विधायक जी विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है और आप कह रहे हैं भाई लोग खिताब दे रहे हैं, भाई लोग प्रशस्तिपत्र दे रहे हैं शिक्षा में सुधाार के लिए, अरे शिक्षा में सुधार के लिए नहीं शिक्षा को बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति होगा कोई मुख्यमंत्री के रुप में होगा, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार होगा, नीतीश कुमार होगा, यही हम कहना चाहते हैं । माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में हमारी सरकार कितनी गंभीर हैं ।

टर्न : 08/कृष्ण/27.11.2019

श्री रामानुज प्रसाद क्रमश : हमारी बिहार की सरकार, माननीय श्री नीतीश कुमार की सरकार, माननीय श्री कृष्ण नन्दन वर्मा की सरकार, कल मैं आपका सुन रहा था, माननीय मंत्री बोल रहे थे, आप कितने गंभीर है । इस राज्य का एक जनप्रतिनधि, एक पूर्व मंत्री भारत सरकार का, एक यहां का राज नेता, एक दल का अध्यक्ष, आमरण अनसन पर बैठा हुआ है, कॉज है शिक्षा में सुधार के लिये । वह कॉज हमें भी मिला । मैं गया था, न कि उनके समर्थन में बल्कि उनकी मांगों को हमने पढ़ा । ये मांग है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे और उस में बाहैसियत शिक्षा राज्य मंत्री,भारत सरकार, उन्होंने जो यहां केन्द्रीय विद्यालय प्रपोज्ड किया था, उसको पास किया था, उसमें बदनियती से सरकार जमीन मुहैया नहीं करा रही है और वह आदमी अनसन पर बैठ करके मरने के लिये आमदा है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नेता बन रहे है । चुनाव है इसलिए ऐसा कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी यह हम आपकी बात सुन रहे थे । कहीं से यह औचित्यपूर्ण नहीं है कि एक राज नेता का दूसरे राज नेता के प्रति इस तरह का वक्तव्य । महोदय, हम ये कहना चाहते हैं । सरकार नवादा में और औरंगाबाद में ये दो विद्यालय हैं, जहां भूमिदाता ने भूमि भी दिये हुये हैं लेकिन आप किन कारणों से जमीन हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं कि वहां केन्द्रीय विद्यालय खुले । क्या आप नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे पढ़े? आप कितने गंभीर हैं ? आपकी गंभीरता और आपकी ईर्ष्या दोनों यहां परिलक्षित होता है । यह हम कहना चाहते हैं । हम आना चाहते हैं सभापति महोदय, यहां जो महामहिम राज्यपाल थे, टंडन जी, उन्होंने स्वीकार किया था । महामहिम टंडन जी ने कहा कि जब मैं अपने यूनिवर्सिटी का मामला ले करके गया, हमारे प्रमंडल में जहां से मैं जनप्रतिनिधि हूं, वहां जे.पी. यूनिवर्सिटी हुआ करता है । वहां 7-8 सत्र से परीक्षा पीछे चल रही है । जब मैं उनसे संपर्क करने गया, उनसे मिलने का काम किया तो उन्होंने कहा कि हम क्या कहें विधायक जी मैं तो बोलता रहता हूं लेकिन यहां की जो शिक्षा व्यवस्था है, वहां के वी.सी. से बात कीजिये वे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं । सारण प्रमंडल में वह यूनिवर्सिटी है और उसका खास्ताहाल है कि पढ़ाई छोड़ कर वहां सारे काम हो रहे हैं । इसको कैसे हम ठीक करेंगे इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, हम शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप हमारे यहां सुधार कीजिये । जो छात्र हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे पास कर रहे हैं, गरीब के बच्चे मैट्रिकुलेशन कर रहे हैं , वे टेंथ पास कर रहे हैं, वे ट्वेल्थ पास कर रहे हैं और वे नामांकन के लिये इधर-उधर भटक रहे हैं । हमलोगों के यहां लोग रोज आ करके कह रहे हैं कि विधायक जी हमारे

बच्चे का नाम लिखवा दीजिये । हमलोग कह रहे हैं और वी.सी. कह रहे हैं कि यह प्रोविजन के हिसाब से हो गया, हमलोग नहीं कर सकते हैं, हमने गवर्नर साहब के यहां भेजा है । माननीय मंत्री जी, इस पर मैं चाहूंगा कि आप इसको संज्ञान में लीजिये और नामांकन कैसे हो या तो सीट बढ़ाया जाय या जबतक सरकार इन्फ्रास्टक्चर नहीं बढ़ा रही है, हम यह मानते हैं कि जनसंख्या की जो विस्फोटक स्थिति है, आधारभूत संरचना हम उतना नहीं बढ़ा रहे हैं तो जो नहीं बढ़ा रहे हैं तो जो है उसको तो सुदृढ़ कीजिये, उसमें तो हम सीट बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें तो हम मानक के हिसाब से शिक्षक देने का काम करेंगे, आप यह करने का काम कीजिये। चाहे नियोजित शिक्षक का मामला हो ।

महोदय, क्रेडिट कार्ड । एक मैं आना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड और एजुकेशन लोन पर । यह बड़ा ही गंभीर मामला है । यह जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और एजुकेशन लोन है, यह बड़ा भेग हो गया है और इससे हमलोग सफर कर रहे हैं । हमलोग मिन्स हमारे लोग । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी तो न्याय के साथ विकास बोलते हैं, हम सामाजिक न्याय के साथ विकास बोलते हैं । तो हम सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, सफरर हो रहे हैं । हमारे जो दलित के बच्ची, हमारे जो अतिपिछड़े की बच्ची, जिनको शौक होता है कि हम टेकनिकल एजुकेशन लें, वे मेडिकल में, इन्जीनियरिंग में एडमिशन दूसरे प्रांतों में ले तो लेते हैं लेकिन जो सरकार के यहां एजुकेशन लोन के लिये प्रयास कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है । कहते हैं कि हम टेकनिकल एजुकेशन में देते हैं, मेडिकल में नहीं हैं । तो उसमें नहीं है आप, आप स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड लो । माननीय मंत्री जी मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य भी सुन रहे हैं, सरकार के लोग सुन रहे हैं, हमारा यह सुझाव है कि सरकार इस पर ऐसी व्यवस्था करे, जो छात्र ऑप्ट करना चाहे स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऑप्ट करे और जो एजुकेशन लोन ऑप्ट करना चाहे, वह एजुकेशन लोन ऑप्ट करे और उसको यह सुविधा हो, यह छूट हो और वहां राशि जाय, यह हम सुझाव के तौर पर सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । थोड़ा और समय दिया जाय । एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो शिक्षकों के जो हालात हैं, हमारे यहां जो लोग ट्रेनिंग करके बैठे हुये हैं, चाहे ऊर्दू टी.ई.टी. के लोग हो या जेनरल टी.ई.टी. के लोग हों, उसमें ज्यादातर चाहे महिलायें हों, चाहे पुरूष हों, सारे

लोग जो इधर-उधर भटक रहे हैं, वे सारे लोग हमलोगों से संपर्क कर रहे हैं, इनकी सरकार जो नियमावली बनायी थी, उस नियमावली के अनुरूप मैं चाहता हूं कि बहालियां हो और वो बहालियां हो करके जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, जो हमारे अपने ही क्षेत्र में हैं, हमने 16 विद्यालयों का नाम गिना दिया, हमारे मित्र माननीय विधायक जी कह रहे हैं, इनके क्षेत्र में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय,तारटोला, नवसृजित प्रावि0,सरांची टोला, प्राथमिक विद्यालय,इस्लामपुर, हम कहना चाहते हैं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री रामानुज प्रसाद : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर गौर फरमाये । सरकार से एक और बात कहना चाहते हैं कि हम अभी देख रहे थे कि रिसोर्सेज के मामले में सरकार की क्या स्थिति हळ । हम देख रहे हैं कि हमारा बिहार, अपने स्रोत से मात्र 24, 25 परसेंट आय करते हैं बाकी केन्द्र से आता है । तो केन्द्र कहीं रीसोर्स देने में आना-कानी करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपनी नीति स्पष्ट करें, आप अपनी नीयत स्पष्ट कीजिये । जैसे कल हमलोगों ने मांग की कि एन.आर.सी. में आप मोदी इफेक्ट में जाईयेगा कि मोदी डिफेक्ट में जाईयेगा ? उसी तरह से केन्द्र से अगर लड़ना हो तो चुनावी जुमला मत बनाईये विशेष राज्य का दर्जा । अगर केन्द्र चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, अगर कटौती कर रहा है, बिहार के साथ बेईमानी कर रहा है, मोदी डिफेक्ट में बिहार सफर कर रहा है तो आप मोदी इफेक्ट में मत पड़िये । बिहार के हित में लड़ने के लिये हम सबलोग साथ देने के लिये तैयार है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: सभापति महोदय, आज शिक्षा के अनुपूरक मांग के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । महोदय आज 4 वर्ष सरकार को बीत गये और जो स्थिति थी, हम कहां से शुरू करें, हमको लग रहा है कि 2005 से ही शुरू करें । महोदय, पूर्व के माननीय सदस्यों ने शिक्षा पर विस्तार से अपनी बातों को रखने का काम किये हैं । लेकिन हमारी सरकार की जो उपलब्धि रही है, जो न्याय के साथ विकास और विकास के साथ शिक्षा के लिये जो उन्होंनें कदम उठाये हैं, उन पर हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में जंगल राज के साथ शिक्षा का कोलाहल था और उसको निपटने के लिये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कदम उठाये गये, उस कदम को हम सराहते थकते नहीं है । महोदय इसलिये नहीं थकते जिस तरह से बिहार में जंगल राज था, बिहार में लॉ एण्ड ऑर्डर खराब था, लोग पढ़ने के लिये जाना नहीं चााहते थे,

विद्यालय की जगह पर चरवाहा विद्यालय खोले जा रहे थे वैसी परिथिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा की एक नीति बनायी और उस नीति के तहत उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के लिये भी सुदृढीकरण किया । वहीं से शुरू किया ।

क्रमश :

टर्न-9/अंजनी/27.11.19

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : क्रमश:... : महोदय, जिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, वहां पर शिक्षकों की बहाली की गयी और विस्तार से बहाली की गयी । मध्य विद्यालय में भी बहाली हुई, उच्च विद्यालय में बहाली हुई । साथ-ही-साथ यह भी देखा गया कि जब बिहार में बदहाली था, जंगल राज था तो उस समय स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, लोग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, बिहार के लोगों को बिहारी कहकर जिस तरह से देश के अन्य राज्यों के लोग हेय दृष्टि से देखते थे कि वहां के लोग तो अशिक्षित हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा में काफी सुधार हुआ, शिक्षकों की बहाली हुई । स्कूल के भवन नहीं थे, हमलोग देखते थे, जिसकी चर्चा वे खुद करते हैं कि पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी लेकिन आज कौन-सा ऐसा स्कूल है जहां पेड़ के नीचे पढ़ाई अभी हो रही है । हम आपका ध्यान उस ओर जाना चाहते हैं कि जब हम 2006 से 2019 को देखते हैं और गांव की ओर जाते हैं और वहां विद्यालय का जब इमारत देखते हैं तो लगता है कि हम नई दिल्ली पहुंच गये । क्या भवन है ? महोदय, सारे विद्यालयों को भवन देने का काम किया गया और इतना-ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे शिक्षकों की बहाली की गयी । लोग कहते हैं कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं । महोदय, 2005 के पहले जिन लोगों ने अपना शिक्षा अध्ययन किया, उसी से न माननीय मुख्यमंत्री जी बहाल करेंगे कि यू0पी0 से मंगा लेंगे या महाराष्ट्र से मंगा लेंगे । तो हम कहना चाहते हैं कि वैसी परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ शिक्षा की ओर ध्यान दिया और दूसरी तरफ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम किया । इसी बिहार से और इसी जगह से शिक्षक के रूप में उन्होंने नियुक्ति देने का काम किया । शिक्षा का विस्तार किया गया, इतना-ही नहीं, जब विद्यार्थी स्कूल में नहीं आते थे तो कहा जाता था कि उनके पास पोशाक नहीं है, किस फटेहाल हाल में जाते, उनकी दशा को देखकर लोगों का रोंवा कलप जाता था कि क्या जंगल राज में हो रहा था ? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके

लिए पोशाक राशि दी, किताब खरीदने के लिए पैसे दिये गये, छात्रवृत्ति दी गयी और इतना ही नहीं, 9वें क्लास के बच्चे/बच्चियों को स्कूल तक पहुंचने के लिए साईकिल दिया गया । साईकिल को जंगल राज में लोग भूल गये थे महोदय । सारी फैक्ट्री बंद हो गयी थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आर्शिवाद से इस तरह के जो कार्य हुए, जिसके कारण छात्र/छात्राओं की संख्या बढ़ गयी । लोग कहते थे कि साईकिल दिया गया लेकिन साईकिल से छात्रायें कैसे स्कूल जायेगी लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि छात्रायें साईकिल पर चढ़कर और बड़ी उमंग के साथ स्कूल जाती हैं और मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, साईकिल देने का, वह बहुत सफल रहा महोदय । महोदय, जब शिक्षा का मजबूतीकरण हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा, सरकार ने सोचा कि पढ़नेवालों की संख्या अधिक हो गयी है, अब तो स्कूल बढ़ाना होगा तो उन्होंने पूरे बिहार में 2019 में सभी पंचायतों में एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर हाई स्कूल में बदलने का काम किया गया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । इसके लिए आपलोग भी सरकार को बधाई दीजिए । महोदय, प्रत्येक पंचायतों में एक हाई स्कूल की स्वीकृति दी गयी और इतना-ही नहीं महोदय, पहले हम लोग सुनते थे कि विदेशों में स्मार्ट क्लास होता है, क्या तो पर्दा लगा रहता है और उसपर पढ़ाई हो जाता है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सपना को भी साकार कर दिया है । स्मार्ट क्लास जिसकी चर्चा हमारे पूर्व के साथियों ने किया । स्मार्ट क्लास क्या है, उसको समझने की जरूरत है । जैसी शिक्षा देना चाहते हैं, देशों का शिक्षा, विदेशों का शिक्षा, हर तरह से उसको देखने का काम कर सकते हैं । सभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने उसको उद्‌घाटन करने का काम किया स्मार्ट क्लास को, जिसके कारण शिक्षा का स्तर बढ़ा । विद्यालयों में प्रयोगशाला के सामानों की मांग हुई तो सभी विद्यालयों में प्रयोगशाला का सामान भेजने का काम किया गया । महोदय, कैसा एजुकेशन है, जहां पर प्रयोगशाला के लिए सारी व्यवस्था, वहां पर जाने की व्यवस्था तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार ने शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक-से-एक कदम उठाये और साथ-ही-साथ शिक्षकों की बहाली के लिए, लोग कह रहे थे कि बहाली चल रहा है तो क्या मामूली बहाली हो रहा है, क्या दो-चार पांच का, लाख में बहाली हो रही है तो लाख शिक्षकों को चुनना कोई आसान काम है क्या ? कहां से उठाकर के, शिक्षकों की नियुक्ति के मापदंड को देखने में भी तो समय लगता है । शिक्षा विभाग पूरी तरह से 2020 के पहले जो सरकार की शिक्षा नीति है, एक-एक विद्यालय में शिक्षक होगा महोदय ।

कोई कमी नहीं रहेगी । एक तरफ सरकारी विद्यालयों में और दूसरी तरफ सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा है महोदय, न्याय के साथ शिक्षा देने का काम किया गया। सरकार ने सोचा कि प्राइवेट विद्यालय भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं बिहार में तो इनके उपर भी इन्होंने ध्यान दिया । प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया, उसकी मंजूरी दी गयी इसी सदन में और आज 9-9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया गया तो इस तरह से इतना बड़ा कदम उठाया गया और उसके बावजूद शिक्षा के प्रति इनलोगों का नजरिया खराब है । महोदय, जहां यूनिवर्सिटी खुल रहा है, जहां टेकनिकल कॉलेजेज खोले जा रहे हैं, पॉलटेकनिक कॉलेजेज खोला गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला ागया, मेडिकल कॉलेज खोला गया, यहां तक कि नर्सिंग स्कूल भी खोले गये । महोदय, सरकारी से हटकर प्राइवेट कालेजेजों की स्वीकृति मिली और प्राइवेट संस्थान भी काम कर रहे हैं । यानी प्राइमरी शिक्षा से लेकर हायर शिक्षा तक पर ध्यान दिया गया । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि पहले मध्य विद्यालय को पार नहीं करते थे चूंकि बैठने का जगह ही नहीं था, मध्य से हाई स्कूल में बदलिए, हाई स्कूल से प्लस-टू और प्लस-टू से स्नातक में गये, और बी0एड0,बी0पी0एड0, तो मैं बताना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण हुआ, जिसके कारण लोग अब बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए । यह सेंट्रल का रिपोर्ट है । महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज लड़कों का इन्तजार कर रहे हैं । वे कहते हैं कि बिहार में क्या हो गया कि बिहार से लड़के लोग नहीं आ रहे हैं । महोदय, बिहार में उच्च शिक्षा प्रणाली में जबर्दस्त उछाल हुआ है और लड़के बिहार से बाहर जाना बंद कर दिये । जब बिहार से बाहर हमलोग लोगों से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बिहार से बाहर के स्कूलों का हालत यह है कि ड्रेस बढ़िया और पढ़ाई खराब । सिर्फ ड्रेस और टाई देखने के लिए ही है बिहार से बाहर । बिहार में जितना अच्छा पोशाक है और उतना ही अच्छा गुणवत्ता के साथ पढ़ाई भी है महोदय । यही हम कहना चाहते हैं ।

....क्रमशः....

टर्न-10/राजेश/27.11.19

श्री चन्द्रसेन प्रसाद, क्रमशः तो लोग कहते हैं कि जा रहे है कहाॅ तो राजस्थान जा रहे हैं, अरे भाई आपलोग स्वतंत्र हैं, राजस्थान के कोटा में पढ़ाईये या जा करके लंदन में पढ़ाईये,

अरे भाई प्रजातंत्र है महोदय, प्रजातंत्र में कुछ लोग, अब अपने आप से नाराज हो जाते हैं कि कोटा काहे भेज दिया, अरे भाई कोटा तो एक ऐसी संस्था है जहॉ लोग देखने के लिए जाते हैं और बिहार के लोग पढ़ते है महोदय, जितना वे मेहनती हैं,उतना ही काम के बदले शिक्षा में भी उतना ही मेहनती है महोदय.......... (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): अब समय आपका दो ही मिनट है, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: इसलिए महोदय मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने नजरिये को बदलिये,जब आप अपना नजरिया को बदलियेगा, तो बिहार के लोग बिहारी को पसंद करना मुनासिब समझेंगे और जो आपलोग कहते हैं कि बिहार में आज शिक्षा ही नहीं है, इसको दिमाग से बदलिये । इसलिए महोदय, बिहार में जो न्याय के साथ विकास और उसी विकास के साथ शिक्षा का जो विकास हुआ है, निश्चित रुप से इसको पूरा देश देख रहा है महोदय । तो जहॉ तक मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा होने जा रहा है, तो हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है,उस विकास के साथ हमारे क्षेत्र की जो समस्या है............. (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, हम एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे । तो महोदय, मैं कहना चाहता हूॅ कि आज बिहार का प्रत्येक विद्यालय अच्छे ढंग से चल रहा है और हमारे क्षेत्र में हम कहना चाहते हैं कि हरेक पंचायत में जो हाईस्कूल को उत्क्रमित किया गया है,हम शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि वहॉ भी कमिटी बनाया जाय,आपने प्रयोगशाला का सामान भेजा लेकिन माननीय विधायकों को सम्मान देने का काम नहीं किया,उनको भी आपको कन्सेंट में लेना चाहिए था माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, तो हम कहना चाहते हैं कि वहॉ भी कमिटी बनायी जाय और कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जहॉ पर भवन नहीं है । महोदय, मेरे क्षेत्र में हैदरपुर एक गॉव है जहॉ पर आबादी कम थी दलितों की लेकिन आज दलितों की आबादी इतना हो गया है कि आज वहॉ पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति दिया जा सकता है । महोदय, एकंगर प्रखंड में हैदरपुर गॉव है, वह प्योर महादलित का गॉव है,वहॉ पर स्कूल खोला जा सकता है,इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपको शुभकामना देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूॅ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण सिंह ।

श्री सत्यनारायण सिंह: सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं । महोदय, अभी हम समझते हैं कि सारे हमारे विद्वान साथियों ने जो चर्चा की, प्रतिपक्ष का मतलब यह नहीं कि सरकार यदि अच्छा काम करें, तो उसका भी विरोध करें । हम समझते हैं कि पूर्व में आप देखते थे विद्यालयों की दशा तो कहीं खपरा दिखाई देता था लेकिन आज हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है,अगर किसी गॉव में गुजरते समय आप देखेंगे कि जहॉं अच्छा भवन हो, लड़के टाईमली क्लास जा रहे हों, तो समझ जाइये कि यह विद्यालय है और जहॉं तक अभी हमारे साथी की बातों पर चर्चा हुई है,अभी हमारे साथी कह रहे थे स्मार्ट क्लासेज का, तो पहले स्लेट और पेंसिल पर जो पढ़ाई होता था और कलम और कागज पर होता था, बड़े-बड़े जो प्राईवेट स्कूल हैं वहॉं स्मार्ट क्लासेज चलते थे, वहॉं कुछ पैसे दे करके पढ़ना पढ़ता था लेकिन जो अभी सरकार है माननीय नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार चल रही है, तो गरीब के बच्चे भी माउस पर रख करके हाथ पढ़ सकते हैं जो पहले अमीर के बच्चे पढ़ते थे, वह गरीब के बच्चे जा करके उससे शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए हम शिक्षा मंत्री जी को अपने आदरणीय नेता माननीय नीतीश कुमार एवं मोदी जी को जितनी प्रशंसा हमारे साथी कर रहे हैं उतना ही कम है, यहॉं तक शिक्षा के मद में ही नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाय, आज हम समझते हैं कि वन एवं पर्यावरण भी है, आप कहीं भी जाइये रोड के किनारे यहॉं से वहॉं तक पेड़, पौधा हरियाली दिखाई दे रहा है । जहॉं तक परिवहन की बात है, पहले हमको डेहरी से आने पर आठ घंटे लगते थे, मगर आज मात्र ढ़ाई से तीन घंटे में मैं आज चला आता हूँ । महोदय, पहले जहॉं एक रास्ता होता था लेकिन अब तो आठ-आठ रास्ते हैं,कहीं से भी आया जा सकता है । जहॉं तक वन की बात है, परिवहन की बात है, सभी डिपार्टमेंट में, अभी हम रहते हैं जहॉं कौटिल्य नगर में, आप जाकर देखें, हर रोड के किनारे वन विभाग के द्वारा .... (व्यवधान)

एडुकेशन तो है ही, एडुकेशन की जितनी भी तारीफ की जाय उतना कम है और हमारे साथियों ने इसकी चर्चा भी किया बल्कि हम यहॉं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे जिसकी चर्चा हमारे रामानुज भाई भी कर रहे थे, हमारे यहॉं भी नामांकन से वंचित कुछ छात्र है बी0ए0 पार्ट वन का, अभी या तो सीट को बढ़ाया जाय या अभी हमारे यहॉं कन्सटीच्वेंट कॉलेज हैं लेकिन उसमें पोटल नहीं खोला गया लेकिन अगर दो चार दिन के लिए परमिशन मिले, तो कुछ बच्चों का एडजस्टमेंट वहॉं हो जायेगा ।

जहॉ तक हमारे क्षेत्र की बात है तो अभी हमारे क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा बल्कि वन विभाग के पदाधिकारी यहॉ होंगे, नगर परिषद् को सिंचाई विभाग के द्वारा पार्क बनाने के लिए 6 एकड़ जमीन आवंटित नगर विकास विभाग को किया गया है लेकिन उसमें वन विभाग के वहॉ पर गाड़ियॉ लगी हुई हैं और सिंचाई विभाग की जमीन वहॉ पर बहुत है, तो मेरा आग्रह होगा कि जो प्लौट एलौटेड है नगर परिषद् को, जिसमें वन विभाग के द्वारा जब्त की गयी गाड़ियॉ वहॉ पर लगी हुई हैं,उसको वहॉ से स्थानान्तरण करके नगर परिषद् को क्लीन चिट दिया जाय और गाड़ियों को वहॉ से हटा दिया जाय, तब जा करके वहॉ पर जो सुंदर सरकार का मंशा है कि वहॉ पर सुंदर पार्क बनें, इसलिए मेरा आग्रह होगा, चूंकि 2010 से गाड़ियॉ वहॉ पर जब्त हैं,वहॉ पर जब्त गाड़ियों की सूची काफी लंबी है बल्कि दो बार उसका टेंडर भी हुआ लेकिन उसका मूल्यांकन करके उसका जो टेंडर किया गया,तो पहले तो उसमें टायर था, ट्यूब था, लेकिन अब टायर, ट्यूब उसमें नहीं है, तो उसका जो अभी रेट है, उस रेट पर कोई भी टेंडरर वहॉ पर एपीयर नहीं हुआ, इसलिए उसको या तो टेंडर करके हटाया जाय या नहीं तो कम से कम 6 एकड़ भूमि जो आवंटित है नगर परिषद् को, उसको वहॉ से हटा दिया जाय । उसीतरह से एक और हमारे यहॉ क्षेत्र की समस्या है, अभी आज वन, परिवहन बल्कि जलवायु परिवर्तन पर भी है, तो मेरा कहना यह है कि आज सोन में खनन के चलते, ऐसा खनन जे0सी0बी0 मशीन से 20 फीट से 30 फीट तक कर रहा है, तो उसके चलते पानी का लेयर बहुत ही नीचे चला गया है ।

क्रमशः

टर्न-11/सत्येन्द्र/27-11-19

श्री सत्यनारायण सिंह(क्रमशः): और परिवहन विभाग के ओवरलोडेड ट्रक के चलते रोड सब जर्जर हो गया है इसलिए मैं परिवहन विभाग के यहां जो पदाधिकारी होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि ओवरलोडिंग पर रोक लगायें और यह कब खत्म होगा ओवरलोडिंग, जितना यहां खनन जो रहा है, उस पर कंट्रोल करने के लिए अगर उस पर कार्रवाई होती है तो संभव है। आज वहां ज्यादा ट्रैक्टर चल रहा है और ट्रैक्टर जो चल रहा है चाहे पी0डब्लू0डी0 का रोड हो या आर0ई0ओ0 का रोड पर, उसी पर खड़ा कर के के उसका लोडिंग करा रहा है जिसके चलते रोड टूट रहा है तो मेरा आग्रह होगा कि जो रोड पर खनन कर के रखा जा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चहिए । सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में एक रामारानी जैन बालिका उच्च विद्यालय है, उस बालिका उच्च

विद्यालय में सरकार के तरफ से काफी सुविधा है लेकिन वहां के प्रधानाध्यापिका के द्वारा जो बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी मनमानी के चलते वह सुविधा वहां के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। वहां के क्लास रूम में पंखा नहीं है जिसे वहां के पदाधिकारी डी0ई0ओ0 भी स्वीकार कर रह हैं। हमारे यहां 27 विद्यालय हैं, सब ठीक हैं लेकिन उसमें से एक विद्यालय की समस्या है । मैं नहीं कहता कि 100 प्रतिशत सुधार हो गया लेकिन आप लोग के समय की तुलना में, आपकी सरकार की तुलना में, उस समय जो 100 प्रतिशत फेल था आज कम से कम 95 प्रतिशत पास है । आज हमारे यहां 27 हाईस्कूल है जबकि उस जमाने में मात्र 13 था और उसमें से मात्र एक का मैं खामी गिना रहा हूँ तो आपके समय से तो अच्छी स्थिति है । महोदय, वहां के डी0ई0ओ0 जाकर के उस विद्यालय में जांच करते हैं और 8 त्रुटि पाते हैं । जब डी0ई0ओ0 जांच करने जाते हैं वहां तो प्रधानाध्यापिका वहां से दूसरी जगह चली जाती है और जो कमियां वहां पायी गयी हैं वह मैं पढ़कर के सुना दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया है। विद्यालय में वर्ग संचालन हेतु कोई समय सारणी विद्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया । प्रधानाध्यापक के बाद दो नियमित शिक्षकों के रहते हुए विद्यालय में पदस्थापित नियोजित शिक्षकों को प्रभार देकर के और खाता का संचालन उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है । छात्र कोष का संचालन वरीय शिक्षक के रहते हुए कनीय शिक्षकों के माध्यम से संचालन किया जा रहा है । विद्यालय का रख रखाव, साफ सफाई आदि की काफी कमी, यह निम्न स्तर का पाया गया । विद्यालय के 9 शौचालय और 5 चापाकल है लेकिन चापाकल चालू हालत में मात्र एक पाया गया, चार का हैंडिल खोलकर रख दिया गया है । वरीय शिक्षिका जो हैं उनकी जगह पर कनीय शिक्षिका के द्वारा काम कराया जा रहा है और महोदय, जब यहां 8-8 कमियां हैं तो वहां के प्रधानाध्यापिका का स्थानांतरण क्यों नहीं हो सकता है इसलिए मेरा सुझाव होगा कि इस पर कार्रवाई हो । महोदय मेरा एक अन्य सुझाव है, योजना एवं विकास विभाग, आज योजना और विकास विभाग भी सम्मिलित है। योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से जो रोड का बन रहा है, उसमें पहले सी0ओ0 से रिपोर्ट लिया जा रहा है और जबतक वह एन0ओ0सी0 सी0ओ0 नहीं देगा, काम रुक जाता है इसलिए मेरा एक मांग है कि सी0ओ0 से जो एन0ओ0सी0 लेना है उसको इससे हटाया जाय । किसी भी विभाग में, जहां तक शिक्षा विभाग की बात करते हैं, आज हर जिले में सरकार की मंशा है कि हर गरीब के बच्चे, अपने ही गांव और अपने पंचायत में ही पढ़ें, उनकी इच्छा है कि हर पंचायत में हाई स्कूल हो और हाईस्कूल को अपग्रेड

कर के इंटर तक करने का काम किया गया है । किसी भी विभाग की बात हो, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में सरकार की जितनी भी तारीफ की जाय, उतना कम है । महोदय, हमारे साथी जो चर्चा कर रहे थे विद्यालय का, हमारे यहां मात्र दो जगह अकोढ़ी गोला में और एक डेहरी में बचा हुआ है, वहां विद्यालय नहीं है, वहां उसका नाम है सेमराडीह वहां विद्यालय नहीं है तो हम चाहेंगे कि सेमराडीह में वहां विद्यालय खोला जाय। हमारे यहां गौतम मध्य विद्यालय है । हमारे यहां दो विद्यालय सभापति महोदय, एक है गौतम मध्य विद्यालय, उसका अपना भवन है, अपना जमीन है लेकिन भवन जर्जर है और मात्र एक कट्ठा उसकी जमीन है लेकिन उस कट्ठा का दाम मिनिमम 50 लाख रू0 है, चूंकि वह मिडिल टाउन में है । अब उसको यहां से रिपोर्ट हो गया है कि वह भवनविहीन है, लेकिन उसका अपना जमीन है इसलिए मेरा आग्रह होगा कि उस भवन को बनवाकर के और विद्यालय को अभी जो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है रामारानी में तो हम चाहेंगे कि उसी में चले और नहीं तो अगल बगल के कोई आदमी उसको कब्जा कर लेगा, इसलिए गौतम मध्य विद्यालय में ही बच्चों को पढ़ाई हो । एक दूसरा विद्यालय है आपको भैंसहा में, वहां चूंकि इरीगेशन की जमीन पर विद्यालय चल रहा था लेकिन अपना जमीन तो उसका है नहीं, जमीन ट्रांसफर के लिए एन0ओ0सी0 नहीं मिला इसलिए उसको भी बगल के विद्यालय मानिकपुर में शिफ्ट कर दिया गया इसलिए मेरा आग्रह है, ऐसे हम लिखे हैं सिंचाई मंत्री जी को कि कम से कम 10 कट्ठा जमीन विद्यालय को दिया जाय लेकिन जबतक यह आवंटित नहीं होता है तब तक उस विद्यालय को मानिकपुर से हटाकर के भैंसहा में ही चलने की अनुमति दी जाय । अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या को रखकर के और जो सरकार नीतीश कुमार जी और मोदी जी के और शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से चल रही है, उसको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री राजेश कुमार जी ।

श्री राजेश कुमार: सभाति महोदय, आज विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ और यह शिक्षा विभाग द्वारा जो द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है उस पर मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ । ऐसे तो समाज का निर्माण, ये शिक्षा को आईना और दर्पण के समान देखा जाता है लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार 2 फरवरी को बजट लायी थी उसमें 13 फरवरी को सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग में 2019-20 के लिए 34 हजार 798 करोड़ रू0 का प्रावधान

हुआ था बजट सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग का था ।(क्रमशः)

टर्न-12/आजाद/27.11.2019

...... क्रमशः ......

श्री राजेश कुमार : और यह दोनों बजट काफी था और विपक्ष से इसका ताला-चाभी मांगी गई और हमलोगों ने सरकार को अपनी तिजोरी का चाभी देने के लिए तैयार हुआ लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग में मैं उदाहरण पेश करना चाहूँगा, अभी हाल में शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश पारित हुआ जिसमें भवनविहिन प्राथमिक विद्यालयों को जहां पर भवन उपलब्ध था, वहां प्राथमिक विद्यालय शिफ्ट करने का आदेश पारित हुआ । लेकिन जब हमलोग क्षेत्रीय भ्रमण में, जिला के भ्रमण में हमलोगों ने पाया कि यह एक तरह से अव्यवहारिक थी, चूँकि यह तुगलकी फरमान, नोटिश जिस तरह से शिक्षा विभाग ने जारी किया और यह मैंने देखा कि तीन-तीन कि0मी0, आपने सही सोचा होगा कि लेकिन आपके पदाधिकारी ए0सी0 रूम में बैठक करके जिस तरह से भवनविहिन प्राथमिक विद्यालयों को आपने शिफ्ट करने का प्रयास किया, आपने कभी नहीं देखा कि 3-3 कि0मी0 क्लास-1 के बच्चे, क्लास-2 के बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे थे, आपने व्यवस्था दिया कि हम आपको भवन में पढ़ायेंगे लेकिन क्या आपने सोचा कि क्लास-3 के बच्चे नाहर, पईन और खेत में लगे फसलों के बीच में 3 कि0मी0 कैसे जायेंगे ? सबसे ज्यादा इसमें गरीब परिवार प्रभावित हुआ और वह गरीब परिवार के बच्चे दुविधा में पड़े रहे कि हम वहां पर अपने बच्चे को कैसे भेजे और 3 कि0मी0, 4 कि0मी0, मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत परता में नारायणपुर से शिफ्ट करके वह जो है पाण्डव बिगहा भेजा गया, यह देखने की चीज है और समझने की चीज है कि बी0आर0सी0 में बैठे आपके शिक्षकों ने 6-6 कि0मी0 के अन्तर पर वह भेज दिया और आज वे बच्चे कहते हैं और उनके माता-पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे थे लेकिन अब विद्यालय जाने से भी कतरा रहे हैं, यह सरकार की आपकी नीति है ? अब मैं आगे आना चाहता हूँ, विद्यालय में स्मार्ट क्लास तो चला दिया, मैं स्वागत करता हूँ कि आपकी सोच सही है लेकिन क्या धरातल पर आपने कहीं न कहीं यह प्रयोग किया कि पूरे विद्यालय में, पूरे सूबे के विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है और एक आप दिवाल पर टी0वी0 लटका देंगे और 75 जी0बी0 का

पेनड्राईव लगा करके आप गति का नियम पढ़ायेंगे कि गति क्या है, यदि हम चलते हैं तो वह गति कहलाती है और जब हम खड़े हैं तो गति नहीं कहलाती है ? आप ऐसे कब तक चलायेंगे स्मार्ट क्लास के थ्रु, एक पेनड्राईव के साथ जब बच्चे हैं और मैंने कई विद्यालयों में गया और वहां जब गया तो देखा कि एक ही पढ़ाई, एक ही चेप्टर गति का नियम, गति का नियम, आपके स्मार्ट क्लास में चल रहे हैं । आप बताईए कि इतना बजट लेकर के आप शिक्षा को ऐसा किये हुए हैं । मैं इस संबंध में सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

आप उन बातों को छोड़िए, आप जिस तरह से सर्व शिक्षा को, आप जे0एन0यू0 में जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से एन0डी0ए0 सरकार आपकी शिक्षा को दुर्दशा कर रही है, शिक्षा का तुष्टीकरण कर रही है, शिक्षा में आर0एस0एस0 को इनवोल्वमेंट कर रहे हैं, आपको जनता कभी माफी नहीं करेगी । आप जो है, आप अभी समझिए । आप बिहार के लोग हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज शिक्षा में आप लाना क्या चाहते हैं ? आप यदि शिक्षा को सुधारना चाहते हैं तो विपक्ष के लोग आपके साथ हैं लेकिन स्वस्थ्य परम्परा, स्वस्थ्य लोकतंत्र का आप यदि नींव रखना चाहते हैं, संसदीय प्रणाली में यह लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का अंग है लेकिन आपकी सरकार ने, डबल ईंजन की सरकार ने विपक्ष को विपक्ष ही समझा है और विपक्ष को आप अगर सही समझते तो विपक्ष भी कुछ सकारात्मक सुझाव देते हैं। चूँकि आप भी जनता के लिए काम करते हैं, आप भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और विपक्ष भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं तो फिर ऐसा भेद-भाव क्यों और यह लोकतंत्र में जिस तरह से विगत 5-6 वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में ह्ास आया है, इसलिए हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जनता सब देख रही है और जनता याद रख रही है । विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं । मैंने देखा है कि सबसे बुरी हालत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे ह्ासमेंट में मारे जाते हैं । हमलोगों ने 13 जिलों का समिति के माध्यम से भ्रमण किया, लेकिन आज जाकर देख लीजिए कि किस हालत में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चे अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में, बालिका आवासीय विद्यालयों में एक भी साईंस का टीचर्स नहीं हैं और हमलोगों ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है, जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह किया है कि वहां पर आप साईंस शिक्षकों का पदस्थापन कीजिए । हमलोगों ने समिति के माध्यम से 13 जिलों का भ्रमण किया है

और इसका प्रतिवेदन दिया है अनुसूचित जाति/जनजाति समिति के द्वारा और उस प्रतिवेदन पर शायद काम हो या नहीं हो लेकिन हमारी समिति ने रिपोर्ट दी है। मैं सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी शिक्षा की बात करते हैं, आप कौन सी क्वालिटी शिक्षा की बात करते हैं कि आपके पास साईंस के टीचर्स नहीं हैं, आपका प्रभारी प्रधानाचार्य से काम चल रहा है, एक विद्यालय 6-7 कि0मी0 की दूरी पर, उसको आप प्रधानाचार्य का प्रभार दे रहे हैं दूसरे विद्यालय में और उसको दे रहे हैं दूसरे विद्यालयों में, आप विद्यालयों को एक प्रभारी टीचर्स भी नहीं दे सकते तो हम समझते हैं कि इतनी बड़ी बजट इस सदन से पास हो रहा है, जिस तरह से सरकार गुमराह करती है और शिक्षा विभाग के बजट पर इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करती है, यह जो है सही मार्गदर्शन में पैसा खर्च नहीं हो रहा है । आप विद्यालयों के चहारदिवारी की बात करें, कई जगह बच्चियों का विद्यालय है, महाविद्यालय है......

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप अब समाप्त करें ।

श्री राजेश कुमार : आप विद्यालय को अपग्रेड कर दिये हैं और वहां के पशु चराने वाले लोग बच्चियों के स्कूल के खिड़की में ......

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, आप अपनी बात शुरू करें ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान मांग पर बोलने का अवसर मिला है । महोदय, शिक्षा पर मैं समझता हूं कि जब तक बिहार में एकल शिक्षा नीति प्रणाली लागू नहीं की जायेगी, तब तक जितनी बात हो रही है, वह समय गंवाने जैसा है। महोदय, मुचकुन दूबे ने स्पष्ट रूप से यह बात कहा है कि शिक्षा नीति एकल नीति होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग कर दिया है, इसलिए इसपर बोलना मैं बहुत जरूरी नहीं समझ रहा हूँ । एक तरफ शिक्षक सड़क पर वेतन के लिए लाठी खा रहे हैं महोदय । राज्य में एक तरफ शिक्षक वेतन के लिए लाठी खा रहे हैं और एक तरफ देश में छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ लाठी खा रहे हैं, यह शिक्षा है आज की । यह मैं महोदय आप से कहना चाहता हूँ । ये फीस वृद्धि करके इन्होंने गरीबों के बच्चे एवं बच्चियों को शिक्षा से बाहर करने का इनका नीति है और इन्होंने इनको बाहर करने का काम किया है महोदय । मैं बहुत पहले से अपने क्षेत्र में 4 वर्षों से एक डिग्री कॉलेज की मांग कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा है । महोदय, जिला मुख्यालय से 40 कि0मी0 दूर यू0पी0 के बोर्डर पर हमारा इलाका है महोदय और

परिणाम होता है कि बच्चे एवं बच्चियां उत्तरप्रदेश जाकर के किसी तरह से डिग्री लेते हैं और जो वहां पर जाने लायक नहीं रहते हैं तो उन गरीबों के बच्चे एवं बच्चियों की पढ़ाई छूट जाती है । यह हालात हैं शिक्षा की । यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज माननीय सदस्य लोग बता रहे थे कि शिक्षक, भवन एवं जमीन के अभाव में 1700 प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर कर दिया गया है, वह कहां जाकर हुआ है, पता नहीं है । महोदय, साथ ही साथ उसमें जो रसोइयां काम कर रही थी, यह बात माननीय मंत्री जी नहीं सुनेंगे, सही बात सुनने का इनका आदत नहीं है । रसोईयां इन सभी लोगों का रोजी-रोटी-रोजगार चला गया महोदय ।

.... क्रमशः ....

टर्न-13/शंभु/27.11.19

श्री सत्यदेव राम : क्रमशः..ये शिक्षा की बात मैं क्या कहूं पूर्वी चम्पारण में सुगौली प्रखंड के बंगला गांव में इस सरकार के ही द्वारा एम0डी0एम0 चलाने के लिए एन0जी0ओ0 के द्वारा ठेका दिया गया है और 16 अक्टूबर को उसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ और 16 नवम्बर को उसका ब्वायलर फट गया जो 57 विद्यालयों के 11 हजार बच्चों को भोजन देना सुनिश्चित था वह आज बंद है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो 13 कर्मचारी कार्यरत थे वे सभी 13 कर्मचारी ब्वायलर के आवाज में सबकी धज्जियां उड़ गयी है और मैं जब गया था तो मात्र 5 पैर दिखायी पड़ा था, बाकी और कोई दिखायी नहीं पड़ा । वहां का जिला प्रशासन इस मामले को दबाने के लिए पूरी कोशिश करके दबा दिया है और पता नहीं चल रहा है कि वह 13 मजदूर कहां है । वह भी शिक्षा का हिस्सा है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार के अंदर शिक्षा के प्रति हमदर्दी है तो मैं मांग करता हूँ कि उन 13 मजदूरों को आज आप इस सदन में स्पष्ट करेंगे कि वह कहां है ?

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : आप एक मिनट में समाप्त कीजिए, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक मिनट में हम अपनी बात समाप्त कर देना चाहते हैं, चूंकि जब मैं बोलता हूँ तो सरकार को लगता है कि सत्यदेव राम विरोध में बोलते हैं, लेकिन मैं यहां विरोध में बोलने के लिए नहीं आया हूँ । मैं यहां आया हूँ कि जो कानून आपने बनाया है वह कानून लागू है कि नहीं है, मैं यह बात कहने आया हूँ । महोदय, खाद्य

सुरक्षा कानून जिसमें प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 5 कि0 अनाज देने का प्रावधान है, अगर सरकार में हिम्मत हो तो बता दे कि हां हम प्रति व्यक्ति को 5 कि0 अनाज देते हैं । हिम्मत हो तो बता दीजिए मैं चैलेंज करता हूँ । कहीं गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है और सर्वे के नाम पर राशन सूची से गरीबों का नाम हर पंचायत में 200 गरीबों का नाम निकाला जा रहा है ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : आप आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक मिनट और सुन लिया जाय । हम इस सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि आप अपने नियम और कानून को देख लीजिए । आपका कोई कानून बिहार में कहीं लागू नहीं है या आप अपना पीठ अपने हाथ से थपथपा लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । इसी तरह से महोदय मनरेगा कानून है । मनरेगा कानून के तहत जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो मांग करते हैं तो उनको 100 दिन काम देना है, लेकिन कहीं बिहार में मनरेगा के तहत काम मजदूरों को नहीं मिल रहा है । 15 अक्टूबर से वह कानून लागू है लेकिन कहीं काम नहीं दिखायी पड़ रहा है । आज ठीकेदार अपने मशीन से काम करा रहे हैं जबकि वर्जित है कि मशीन से काम नहीं करना है । हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप मनरेगा कानून में एक तो काम दीजिए और साथ ही साथ जो मनरेगा कानून में न्यूनतम मजदूरी है उसको लागू कीजिए। मनरेगा में क्या आप पैसा देते हैं 177 रू0 आपको यह बताना पड़ेगा कि 177 रू0 में कैसे कोई गरीब आदमी अपना जीवन बसर कर सकता है ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : आप आप समाप्त कीजिए.....सत्यदेव जी आपकी कोई बात अब कार्यवाही में नहीं जा रही है । अभी-अभी माननीय सदस्य जीतकर आये हैं इनको अपना वक्तव्य देने दीजिए । श्री रामदेव यादव जी प्रारंभ कीजिए ।

श्री रामदेव यादव : सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज मुख्य रूप से शिक्षा विभाग पर चर्चा हो रही है और कई माननीय सदस्यों ने इसपर प्रकाश डाला है । हमें तो लगता है कि सचमुच में बिहार में शिक्षा में व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है । सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन हम एक उदाहरण देना चाहते हैं । हमारे ही विधान सभा क्षेत्र में कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय जो वर्षों से माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल से चल रहा था उसका कोड ही खतम कर दिया, वहां की बच्चियों को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है । ऐसी सरकार है और उनका कोड समाप्त कर दिया गया । इसके अलावे जो उच्च विद्यालय है मेरे क्षेत्र में बेलहर उच्च

विद्यालय हो या सुइया उच्च विद्यालय, खेसर उच्च विद्यालय, गौड़ा उच्च विद्यालय, बेलहर साहेबगंज उच्च विद्यालय, बेलडीहा उच्च विद्यालय इन सभी उच्च विद्यालयों में मैं गया था जब चुनाव में घूम रहा था तो एक शिक्षक के आधार पर कई स्कूलों को मैंने देखा सिर्फ एक ही, कहीं दो नहीं तो एक शिक्षक और इस तरह का नारा देकर के कैसे शिक्षा व्यवस्था में सरकार सुधार लायेगी । मैं समझता हूँ और माननीय मंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि आज के भाषण में आप बतायें कि ये प्रोजेक्ट विद्यालय जो 25-30 वर्षों से चल रहा था, क्यों बंद हुआ ? क्या गुनाह है वहां की बच्चियों का ? आप जानते हैं बेलहर विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहां की बच्चियों को आज पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, उसके स्कूल का कोड ही रद्द कर दिया गया है । इसके अलावे जहां तक गुणवत्ता की बात हो रही है, शिक्षक नियोजन की जहां तक बात हो रही है, समान शिक्षा पर हमलोगों के आवास को भी घेरा गया था । मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि नियोजित शिक्षक की मांग को पूरा किया जाय । उनकी जो मांग है समान शिक्षा के माध्यम से, समान वेतन उनको भी दिया जाय । यह मांग मैं करना चाहता हूँ। जहां तक गुणवत्ता की बात है तो शिक्षकों में भी काफी गुणवत्ता की कमी देखी गयी है । क्षेत्रों पर इस विषय पर हम आपको कहना चाहते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग से बहाली किया जाय ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल सके । अभी जो शिक्षक दिये जा रहे हैं, जो बहाली हो रही है जो पंचायतों से हो रहा है, जो जिला परिषद् से हो रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमारे बच्चों को नहीं मिलता, बिहार के लोगों को नहीं मिलता इसलिए शिक्षा में सुधार के लिए हम चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आप बहाल करें । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ पहले भी मैंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हमारे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है । हमारा प्रखंड फुलीडुमर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, चानन में कोई नहीं है, बेलहर में कोई नहीं है । इस तरह की बात है और प्लस टू विद्यालय कई पंचायतों में हमारे यहां नहीं है । फुलीडुमर प्रखंड के कैथा पंचायत, गोरा पंचायत, राइता पंचायत इन सब जगहों पर प्लस टू विद्यालय नहीं है । मैं शिक्षा मंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि इसमें भी प्लट टू विद्यालय खोला जाय उनको मान्यता दिया जाय । दूसरी तरफ मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ महोदय कि बेलहर में पुलिस अनुमंडल का दर्जा सृजित किया गया है तो डी0एस0पी0 को वहां बैठना चाहिए, लेकिन वह बेलहर में नहीं बैठकर के ये दूसरे अन्य जगह कटोरिया में वहां के एस0डी0पी0ओ0, डी0एस0पी0 बैठते हैं । क्रमशः

टर्न-14:ज्योति:27-11-2019

क्रमश:

श्री रामदेव यादव : जबकि बेलहर काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहॉ जो उच्च पदाधिकारी हैं डी. एस.पी. को बेलहर में बैठना चाहिए था वह बेलहर में नहीं बैठते हैं जिसके कारण वहॉ नक्सल लोग काफी लोगों को तबाह और तंग करते हैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं महोदय, माननीय मंत्री जी से कि वहॉ जो पुलिस अनुमंडल का जो दर्जा बेलहर में दिया गया है उसे बेलहर में ही बैठने का आदेश पारित सरकार द्वारा किया जाय । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूॅं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब जनता दल यूनाईटेड के माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅं । महोदय,....

सभापति (श्री मो0 नेमतुललाह) : 10 मिनट टाईप है आपको ।

श्री ललन पासवान : सर, सर , पॉचों मिनट में चलेगा, आप चिन्ता मत कीजिये सर । महोदय, कई तरह की बात हुई, भाषण हुए, सामाजिक न्याय समतामूलक, बहुत तरह की बातें हुई महोदय । दरअसल महोदय, हमारे देखने से और पढ़ने से पता चलता है कि बिहार प्रयोगशाला और पाठशाला है । लोकतंत्र का पाठशाला और प्रयोगशाला है। ज्ञान का धर्मो का परिवर्तन का आजादी की लड़ाई का कई प्रयोग यहॉ इस बिहार में हुए हैं लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात तब आती है । हालांकि लोकतंत्र में पार्टियों का सभी पार्टियों का घर शीशे का होता है लेकिन अब विचारों की राजनीति कम होती है, सिद्धांतो की राजनीति कम होती है । भाषण ज्यादा होता है, भाषण तब होता है । महाराष्ट्र पर क्यों पूछते हैं हम बताते हैं आपको । भाषण तब होता है जब अवसर मिलता है मनुष्य को कर्म करने का और रास्ता पर लकीर खींचने का तो इस भूमि पर राजगीर से लेकर पाटलिपुत्र तक एक से एक वंश आए जिन्होंने बड़ी बड़ी लकीरें खींची । 55 साल कौंग्रेस रही महोदय, और जब रही तो श्री बाबू के समय से यात्रा शुरु किया जाय अंतिम तक तो माननीय ललित यादव तक यात्रा समाप्त करते हैं हम अगर तो आप अगर बात करियेगा तो जो विरासत थी इस मिट्टी की वह विरासत इन लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया, उसमें न विचार रहा, न विकास रहा न सिद्धांत रहा

और जब बात बिगड़ गयी तो अब लोग छाती पिटते हैं महोदय, नीतीश कुमार जी की बारी आई 2005 में । हम उस समय थे । हम उस समय एम.एल.ए. थे । विचारों का मतभेद होता है मन भेद नहीं होता है । विचारों का मतभेद हुआ तो निश्चित तौर से मेरी लड़ाई हुई थी मैं ठोक कर कहता हूॅं लेकिन जो काम हुए थे, काम की चर्चा तो होती ही है । पहली बार बिहार में 2005 में 1000 स्कूल उत्क्रमित हुआ 10 प्लस टू में महोदय । हुआ तो शुरुआत, यात्रा की जाती है, कुछ बात कही जायेगी कि अतिश्योक्ति नहीं कि एक बार बहाली हुई थी 25 हजार शिक्षकों की और निश्चित तौर से यह बात कही जाती और यह प्रशंसा की बात हो सकती थी लेकिन बाकी दिनों में राज्य में जो शिक्षा का जो पतन हुआ उसके लिए काई एक व्यक्ति बोलने वाला नहीं है और एक व्यक्ति नहीं पूरी सरकार उस कटघरे में खड़ी थी और दो साल पहले ढाई साल पहले ये भी लोग इधर ही थपड़ी बजा रहे थे, हम लोग उधर बजा रहे थे लेकिन उस समय बड़ाई कर रहे थे अभी जब वर्णन कर रहे थे सामाजिक न्याय का सूरज अब इस देश में डूबने वाला है और सामाजिक न्याय की जो परेशानी की जो चर्चा करते हैं जिनको चिन्ता है लोकतंत्र में वे सामाजिक न्याय परिवारवाद और जातिवाद में तब्दील हो गया । गरीब, दलित, शोषित उपेक्षित रह गया, यह सामाजिक न्याय की परिभाषा परिभाषित हुई देश में इसलिए महोदय, शिक्षा पर अगर चर्चा करेंगे इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं । जब सामाजिक न्याय लागू हुआ था वाकई में सामाजिक न्याय इस देश में बी.पी.सिंह. के नेतृत्व में हो गया होता तो यहां किसी को कटोरा लेकर भीख मांगने का काम नहीं करना होता । लोगों ने माल भरने का काम किया, जात को मजबूत किया और क्या क्या लोग किया इसलिए मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूॅं । चर्चा करने पर लोग नंगा हो जायेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूॅं कि सामाजिक न्याय की परिभाषा में गरीब होता है, दलित और शोषित भी होता है और अति पिछड़ा भी होता है और अति पिछड़ो की भूख जगी सामाजिक न्याय में, दलितों की भूख जगी सामाजिक न्याय में लेकिन उसके पेट पर लात पड़ा, सामाजिक न्याय आज तक नहीं मिला, न जाने कई सौ वर्षों के बाद मिलेगा हमको नहीं पता है । कौन आयेगा इसलिए महोदय, हम चुआड़ी की पानी पर चर्चा करें । अरे, 70 वर्षों में आप तो कभी नहीं गए । गया तो नीतीश कुमार 6 अप्रील 2018 को और गया तो मैं उस दिन भी कहा था कि भाई आप से कम शक्ति जी और ललित यादव जी आप से कम वहॉं मजबूत यादव नहीं रहता है, आपसे गोरा गोरा यादव रहता है और सब गरीब जा कर 12 कि. मी. चुआड़ी का पानी लाता है और वहॉं 22 वेल पम्प सोलर करवाये । 22 वेल पम्प

सोलर और थाना भी बनने जा रहा है अब उसकी चर्चा अब अधौरा से लेकर यहॉ तक सड़क बन गयी इसलिए वह सब कौंग्रेस और उसकी चर्चा मत करिये । विकास पर चर्चा करना बेकार बात है, बेमानी है । सामाजिक न्याय की बात तो बलिदान देने की ताकत है क्या ? बलिदान आप नहीं दीजियेगा माल भी मारियेगा और सामाजिक न्याय की चर्चा करियेगा ऐसे नहीं चलने वाला है इसलिए बलिदान दीजिये । मान लीजिये न । कहां मानियेगा कलेजा में दम है मानने का , नहीं मानियेगा और नीतीश कुमार इस सामाजिक न्याय का इस देश में अंतिम चिराग है । लोहिया, कूर्परी , जयप्रकायश कोई जिन्दा नहीं है, मुलायम सिंह अंतिम कगार पर जिनकी चर्चा कर रहे हैं अब मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं मैं भी मानता हूँ सामाजिक न्याय के अंश में वह दूसरी जगह खड़ा हैं और बाकी में सामाजिक न्याय की आग नहीं जलती है दूसरी आग जलती है उस आग से इस देश में सामाजिक न्याय नहीं लागू होगा । उसमें पीड़ा और दर्द गरीबों का दलितों का दूर नहीं होगा। चांदी के चम्मच वालों से सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा । सामाजिक न्याय जिसके कलेजे में दर्द है और जो गरीब दलित मुशहरों के घरां में पानी पिया है वही सामाजिक न्याय देगा सत्ता में आने से सामाजिक न्याय आप नहीं दीजियेगा । टोला सेवक और कौन कौन सेवक का काम अगर कोई किया तो नीतीश कुमार ने किया यह तो पक्ष और विपक्ष में आज नहीं तो कल कहना ही पड़ेगा । इसलिए महोदय, अरे हम यहां रहे या वहॉ रहें हम साफ साफ बोलते हैं हमारे कटने और जपने की बात नहीं हैं राजेश जी, इसलिए आप देखें । इसलिए महोदय, समय का अभाव है । हम आपको कहना चाहते हैं और महोदय, ये लाल सलाम । मैं कहा कि महोदय, साम्यवाद और समाजवाद का भारत से सूरज डूबने जा रहा है । किन्हीं लोगों ने बलिदान देने का काम नहीं किया और विचारों की राजनीति मरने वाली है । लोहिया, जयप्रकाश और अब जौर्ज नहीं रहे कृपलानी नहीं रहे ज्योतिबा फूले नहीं रहे और ये लाल सलाम करते करते पूरे गरीबों को खत्म कर दिये । इसलिए महोदय, हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर से विकास की लकीर खींची गयी है। हो सकता है कि कुछ छोटी हो आज नहीं कल बड़ी हो जायेगी । शिक्षा में निश्चित तौर से जो विद्यालय हम अपने चेनारी में 2005 में 395 स्कूल खुला था, 219 स्कूल प्राथमिक विद्यालय चेनारी में 2005 में पहली बार बना था यह बात मुझे कहना ही पड़ेगा चाहे इधर से कहूँ या उधर से कहूं । अकेले मैं था जहॉ ये बनवाया था रोहतास जिला में चेनारी विधान सभा में जहॉ पेड़ के नीचे दलितों और शोषितों के बच्चे पढ़ते थे । हॉ दो चार गांव बचा है । 2005 में बनवाये थे । महोदय, हमारे यहॉ भी कुछ गांव बचा

है चर्चा कर दिए तो एक मुशहरी टोला उगहनी गांव है, उगहनी गांव मे स्कूल है दो विद्यालय है लेकिन कुछ दूरी पर सड़क भी बना दिए, सामुदायिक भवन बना दिए, बिजली ले गए लेकिन उगहनी में मुशहर समाज के लोगों के लिए प्राथमिक विद्यालय हम कहेंगे मंत्री जी से कि लिखिये और एक चिखूरिया गांव हैं पासवान और पंडित जी का गांव है महोदय, एक नींव गोंव है, एक बेलसीर गांव है गिरीहरी गांव है मगरदह मुशहर का गांव है और ये पॉच गांव है और हम कहेंगे कि यह सर्व शिक्षा अभियान में पैसा देना बंद कर दिया गया है तो प्राथमिक विद्यालय बनना और नियम बदल दिया गया। महोदय, हम सबसे बड़ी बात आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने साईकिल योजना, पोशाक योजना कई विद्यालय उत्क्रमित किए हमाराभी अनूसूचित जाति जन जाति का लंबे दिनों के आजादी के 70 वर्षों के बाद एक कुदरा में 10 प्लस टू विद्यालय था जहॉ से आज भी निरंजन राम जी माननीय विधायक ले गए हैं उसी विद्यार्थी को जो पढ़ रहा था उसमें वही पढ़ा था, बी.बी.एस.सी. में कंपीट किया, उसमें वह भी आज कुदरा में बी.डी.ओ. है तो महोदय, पहले तो उस विद्यालय 60 अनुसूचित जाति का विद्यालय हुआ है, मैं एक बात सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूॅ 3-4 स्कूल हैं जहॉ 10 प्लस टू है जहॉ कमरे हैं पढ़ाईयां होती है लेकिन शिक्षक निश्चित तौर से 10 प्लस टू में शिक्षकों का सरकार स्वयं गछती है और झूठ नहीं बोलती है सरकार , सरकार गछती है कि हम 10 प्लस टू में शिक्षक बहाली कर रहे हैं । क्रमशः

टर्न : 15/कृष्ण/27.11.2019

श्री ललन पासवान (क्रमशः) झूठ नहीं बोलती है सरकार, सरकार गछती है कि टेंथ प्लस टू में हम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं । हमारे यहां टेंड प्लस टू विद्यालय है, 4 हजार बच्चे बच्चियां हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं । उच्च विद्यालय मोहनियां हैं, उच्च विद्यालय,राजपुर है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य आप समाप्त कीजिये ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, एक मिनट । उच्च विद्यालय,अमझोर हैं, कन्या उच्च विद्यालय है, रामदुलारी है, चेनारी है, सदोखर है और आलमपुर है ।

महोदय, हम एक दूसरी बात भी कहना चाहते हैं । सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां होते और अगर कहीं सुन रहे हैं तो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, गया, मगध में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हुआ है लेकिन पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं मिली है । महोदय, मैं पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारे यहां बड़ी आबादी है लगभग एक करोड़ की

आबादी है, रोहतास, भभुआ, भोजपुर और बक्सर । हम कहना चाहते हैं कि सरकार अनुमोदन करे और उस इलाके में बाबा साहब अम्बेदकर के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कैमूर और भभुआ में करायें । हम आपके माध्यम से सरकार से मांग भी करते हैं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया । अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी । आप अपना वक्तव्य शुरू कीजिये । आपका 11 मिनट समय है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, मैं दिनकर जी की दो पंक्तियों के साथ अपना निवेदन प्रारम्भ करूंगा ।

महोदय, मैं काफी देर से माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था और मुझे आश्चर्य होता है कि जब दिनकर के बिहार में और बिहार विधान सभा में जब हम शिक्षा पर बहस कर रहें हो तो बहस का स्तर कैसा होना चाहिए । तो मैंने दिनकर जी की दो पंक्तियां लिखी है -

"अंधा चकाचौध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा ।
साक्षी है उसकी महिमा की, सूर्य, चन्द्र, खगोल, भूगोल,
कलम आज उसकी जय बोल । "

यह दिनकर जी ने लिखा है । जिन के ऊपर लिखा है, वे समझ गये होंगे । मैं इसके आगे माननीय अटल जी की भी मैं एक पंक्ति कहूंगा बिहार के बारे में । माननीय अटज जी ने बिहार के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी थी -

"मैं अखिल विश्व का गुरू महान,देता विद्या का अमरदान,
मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्मज्ञान,
मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर,
मानव के मन का अंधकार, क्या कभी सामने सका ठहर ।"

यही बिहार है महोदय और उस बिहार पर हम चर्चा करने के लिये खड़े हुये हैं । महोदय, हमारे विपक्ष के एक साथी कह रहे थे, बिहार विधान सभा के सदन में बैठे हैं और मोदी इफेक्ट और मोदी डिफेक्ट की चर्चा हो रही है । एक महाराष्ट्रा का खेल गड़बड़ा गया, उत्साह का वातावरण आ गया लेकिन आप कर्नाटक मत भूलिये । कर्नाटक भी ध्यान में रखियेगा । सभापति महोदय, यह तो बिहार विधान सभा में ही हुआ है कि अगला चुनाव माननीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ लड़कर

आये और श्री नीतीश जी हमलोगों के साथ बैठ गये और ये लोग उधर चले गये और यह पीड़ा बराबर इनको पीड़ित करते रहती है । जहां मुद्दे की बात होती है, वहां नहीं बोलते हैं, दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं ।

महोदय, मैं यह सदन को बताना चाहूंगा कि बिहार में 90 परसेंट बच्चे स्कूलों में नामांकित हो चुके हैं और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढते हैं, यह पहले नहीं होता था, जो आज बिहार में हो रहा है । महोदय, मुख्य मंत्री बालिका इन्टर प्रोत्साहन योजनाा 10 हजार की राशि, क्या पहले कभी किसी सरकार में मिलती थी ? यह बिहार की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की देन है कि बिहार की बच्चियों को स्कूल तक ले जाने के लिये इतनी बड़ी योजनायें चलायी गयी और उसका फायदा यह हुआ कि 2019 के माध्यमिक परीक्षा में, मैट्रिक में 83. 19 परसेंट छात्र, 76.1 परसेंट छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की । इन्टर में 77.58 छात्र और 79.80 छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की । महोदय, यह बिहार के लिये बहुत बड़ी बात है ।

महोदय, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री इसी बिहार में , बिहार में जब लड़कियां स्कूल जाने के लिये निकलती थी तो क्या हालात थे ? माता-पिता अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे । वे सोचते थे कि पता नहीं बाहर में क्या हो जायेगा आरै आज तब बिहार की बेटियां साईकिल पर चढ़ करके और घंटी बजाते हुये स्कूल जाती हैं तो देखनेवाला व्यक्ति एन.डी.ए. जिंदाबाद का नारा लगाता है । यह बिहार में हो रहा है।

महोदय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है । गरीब के बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बिहार की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू करके 20218-19 में 43,336 विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिये ऋण स्वीकृत किया, महोदय, यह अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है ।

महोदय, पूर्व में हमारे बिहार में 13 विश्व विद्यालय थे । अब तो बिहार में 7 प्राईवेट यूनिवर्सिटी खुले हैं । पहले क्यों नहीं खुलते थे ? महोदय, डर के मारे बिहार से बाहर का कोई भी व्यक्ति बिहार में इसलिए इन्स्टीच्यूशन नहीं खोलता था कि इंस्टीच्यूशन खोलने से पहले उसके पास टेलिफोन पहुंच जाता था, रैन्सम का डिमांड हो जाता था । लेकिन महोदय, अब यह बिहार बदल गया है और बिहार आज आगे बढ़ रहा है । आज अमेटी यूनिवर्सिटी का ब्रांच पटना में, संदीप फाउन्डेशन, के0 के0 बिड़ला, सी.बी.रमण जैसे इन्स्टीच्यूट आज पटना में है । तकनीकी शिक्षा हेतु

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यलाय और नैनो टेकनोलॉजी पर चर्चा बिहार में हो रही है और महोदय, यह सब लोगों को स्वीकार करना चाहिये ।

महोदय, दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना । बच्चे शाम के समय जब अपने घरों में पढ़ने जाते थे तो वे लालटेन जलाकर पढ़ा करते थे और आज लालटेन युग का समापन हो गया । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से आज एक-एक घर में बिजली पहुंच गयी और अब तो हम खेतों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं । मेरा समय थोड़ा काट दिया गया । लेकिन मेरा सुझाव तो ले लीजिये महोदय ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप लिखित दे दीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, बिहार में 69 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मदरसा को अनुदान लगातर मिल रहा है और संस्कृत विद्यालय जो 69 हैं, उसका अनुदान रोका गया है । आप के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि 69 संस्कृत विद्यालय को अनुदान तुरंत जारी किया जाय ।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, आज जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखने का काम किये हैं और खास करके सत्ता पक्ष में बैठे जो हमारी भाई हैं, माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी जी महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हुये थोड़ा उनको शर्म भी करना चाहिए कि इन्होंने क्या करके पूरे देश में क्या पहचान बनाई है ।

महोदय, आज जो शिक्षा की स्थिति बनी हुई है, माननीय मंत्री बैठे हुये हैं, बद से बदत्तर स्थिति बिहार में बनी हुई हळ । माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के बोलते हैं, सरकार का गुणगान करते हैं , नियम-प्रक्रिया है उसके अंतर्गत काम करते हैं । लेकिन निश्चित रूप से अपने सीने पर हाथ रख कर कहें कि खास करके माननीय विधायक को प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया और वैसी परिस्थिति में जो सारे जगह उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनाये गये, उसमें अभी तक कमिटी नहीं बनी, जहां पर हाई स्कूल है, वहां पर कमिटी बनी बनी, अगर बनी भी तो उसके हेड मास्टर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि हमको ऊपर से आदेश आया है कि हमको अपने

मर्जी से कुछ करना है । यह हाल माननीय सदस्यों का हुआ है । जिस तरीके के शिक्षक के बारे में, हमलोग बोला करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि –

"जबतक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है । "

महोदय, समान काम के लिये समान वेतन, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को जिनके जमाने में जो शिक्षक बहाल हुये आज वह 80 हजार पा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जमाने में जो शिक्षक बहाल हुये, उनको आज 20 हजार मिल रहा है । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी ने दिनकर जी की पंक्तियों की बात की हैं तो हम भी दिनकर जी एक पंक्ति कहना चाहते हैं :

" फेक दो उस पत्थर को जिस पत्थर में छेद रहे,
जला तो उस लंका को जहां भाई-भाई में भेद रहे । "

इस तरह की नीतियां नहीं चलेगी । एक ही स्कूल में राम का दो बेटा श्याम और पवन शिक्षक हैं । लालू जी के जमाने में पवन बहाल हुआ तो उनको 80 हजार और नीतीश जी के जमाने में बहाल हुया श्याम तो उनको उसी स्कूल में 20 हजार । एक तरह का काम करनेवाले को दो तरह का वेतन । सभापति महादय, यह नहीं चलेगा ।

क्रमश :

टर्न-16/अंजनी/27.11.19

श्री शिवचन्द्र राम... क्रमशः ..... नीति में सुधार करना पड़ेगा । यही नहीं, जो स्थितियां बन रही है, अभी प्रैक्टिकल का बात किया जा रहा है, तमाम् हाई स्कूल में माननीय सदस्य अध्यक्ष हुआ करते हैं, प्रैक्टिकल का सामान खरीद लिया गया, कहां से सामान खरीदा, कैसा सामान खरीदा, किस तरीके का है, कहां बेच दिया, इसका कोई अता-पता नहीं है । शिक्षा मंत्री जी आप पहले माननीय हैं, उसके बाद मंत्री हैं। आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और कम-से-कम बिहार के जो अभी प्रधान सचिव हैं को बैठाकर इसपर संज्ञान लें और माननीय सदस्य को अगर उनसे नहीं संभलता है तो उनको प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाय । एक दूसरा लेटर निकाला जाय, अगर नहीं अध्यक्ष रहे तो कम-से-कम उनको पावर दिया जाय, अधिकार दिया जाय, नही तो वे अपना नियम बनाये कि प्रबंध समिति में जो पैसे आये हैं, उसको हम अपने विभाग से खर्च कराने का काम करेंगे । पैसा खर्च तो होता नहीं है और माननीय सदस्य जो सदस्य हैं, उनके उपर उंगुलियां उठती है कि उनकी बात नहीं माना जाता है, इसलिए

इन तमाम् मुद्दों को सरकार को देखना चाहिए । साथ-ही-साथ, टोला सेवक का मामला है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, टोला सेवक जितना काम कर रहा है, बहादुरी की बात हो रही है कि हमने टोला सेवक का बहाली किया, हमने तालिमी वर्कर की बहाली किया लेकिन उनके साथ आज क्या हो रहा है ? पांच हजार, सात हजार रूपया से क्या उनका रोजी-रोटी चल सकता है ? क्या यही स्थिति बन गयी है ? ऐसी परिस्थिति में टोला सेवक जो तालिमी वर्कर हैं, उनका मानदेय कम-से-कम 25 हजार रूपया माननीय मंत्री जी को बढ़ाना चाहिए । साथ-ही-साथ, यह कहना चाहते हैं, अभी पासवान जी बात कर रहे थे, अभी वे सदन में नहीं हैं, हम कहना चाहते हैं कि कम-से-कम बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर जी का प्रतिमा विधान परिसर में लगायी जाय और इसपर विचार किया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहेब, दो-तीन मिनट ही समय आप लेना चाहते हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : 5-6 मिनट चाहिए ।

अध्यक्ष : यह समय कुछ ज्यादा हो जायेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : पांच मिनट समय दिया जाय । महोदय, द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में हमलोग शिक्षा विभाग के बहस तक ही सीमित हैं, अन्य विभाग गिलोटीन में है, इसलिए उसकी चर्चा करना मुनासिब भी नहीं है । अब चूंकि कृष्णनंदन वर्मा जी हैं.....

अध्यक्ष : लगता है कि आप पूरी तैयारी से हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : जी हां । हम जानते हैं, हम माननीय मंत्री जी के काबिलियत से वाकिफ हैं । महोदय, यहां बहुत सारे लोग वैसे बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, जिन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किया था । मैं तो यही कहूंगा कि कर्पूरी जी ने इसी हाउस में एक बार कहा कि मैं उस केडर के अफसर का नाम नहीं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि तीन केटेगरी के पदाधिकारी हैं - एक केटेगरी है देवतातुल्य का, दूसरा केटेगरी है नपुंसकों का और तीसरा केटेगरी है भटियारों का तो अब जो सत्ता पक्ष में हैं, उनका दायित्व है कि सरकार की उपलब्धियों को बताना, नीति और कैसे प्रखर हो, उसको बताना और विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को उजागर करना, मगर अब कुछ आदमी तो जो नये-नये मुसलमान हुए, वे दनादन प्याज खा रहे हैं और खायें प्याज,

अध्यक्ष : प्याज इसलिए महंगा हो गया है क्या ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : पता नहीं हो सकता है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, कुछ लोग प्याज खा ही नहीं रहे हैं बल्कि प्याज का माला भी पहन रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मगर जो नमक खाया तो उसका असर इतना जल्दी खत्म हो जायेगा, यह हमलोगों की समझ में नहीं आता है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी युवजन सभा से अपनी राजनीति की शुरूआत की थी और उक्त लोग, समाजवादी लोग नारा लगाते थे कि राजा हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान । खैर, अब जो दौर बदला, उसमें बहुत हद तक संभव नहीं है । महोदय, अब हमारे पास जो बंटा हुआ शिक्षा है- प्राइमरी शिक्षा, सेकेंड्री शिक्षा, हायर एजुकेशन वगैरह-वगैरह । उसी तरह नवसृजित विद्यालय हैं, बुनियादी विद्यालय हैं, अल्पसंख्यक विद्यालय हैं और उसी तरह टीचर भी तीन-चार केटेगरी के हो गये हैं । हाई स्कूल में होता था साईंस टीचर, आर्टस टीचर, उर्दू टीचर, फारसी टीचर मगर अब शिक्षक क्या हो गया- एक हो गया अतिथि शिक्षक, एक शिक्षक हो गया नियोजित शिक्षक और एक शिक्षक हो गया नियमित शिक्षक । अब तीनों का एक तरह से करेक्टर बदला हुआ है वेतन का और फलांने का तो मैं चाहूंगा कि शिक्षक एक तरह का हाई स्कूल में हो, जैसे-साईंस टीचर होते थे, आर्टस टीचर होते थे, हिन्दी टीचर होते थे, एक तरह का हो । महोदय, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को मदद कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : अच्छी बात है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, उसी तरह स्कूल जो है, हाई स्कूल है, कॉलेज है फिर सेकेंड्री स्कूल है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि बुनियादी विद्यालय के संबंध में मैंने पिछले सत्र में कहा था और आपने 150वीं जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मनाने का जिक्र किया था तो आज कम-से-कम बता दीजिए कि आज बुनियादी स्कूल की क्या स्थिति है और आप क्या करने जा रहे हैं और जो स्कूलें हैं आपकी उसमें आपके सबजेक्टवाइज टीचर है या नहीं ? उदाहरणस्वरूप, जो प्रीमियर इन्स्टीच्यूसन कहलाता था, उसमें कितने नियमित शिक्षक हैं और कितने अतिथि शिक्षक हैं, यह आप बता दीजिए । उसी तरह जब सब्जेक्टवाइज कहते हैं तो उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी का शिक्षक हुआ करते थे, खैर अब संगत में अरबी, फारसी और उर्दू का टीचर नहीं बहाल कर रहे हैं तो समझ में आता है कि संगत का असर है या डर है लेकिन कम-से-कम संस्कृत शिक्षक का तो बहाल कर दीजिए ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं यह कहकर समाप्त करता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, आप अपनी बड़ाई, अपनी पीठ अपने खुद नहीं थपथपाना चाहिए, अगर ऑपोजीशन थपथपाये तो समझिए कि कुछ काम हुआ है । आप एक बार दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल का स्कूल व्यवस्था देखकर आइए और तब आप बैठकर गंभीरता से निर्णय लीजिएगा कि अब आप कहां तक पहुंचे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेमतुल्लाह जी एक मिनट ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मैं सिर्फ मदरसा के बारे में बोलना चाहता हूँ । किसी सदस्य ने नहीं बोला है, इसलिए कि 259 मदरसा...

अध्यक्ष : यह बात आप सिद्दिकी साहेब को कह रहे हैं ?

श्री मो0 नेमतुल्लाह : जी नहीं, मैं सारे माननीय सदस्य को कह रहा हूँ । आठ साल में, 2011 में सिर्फ 814 मदरसे का एफिलियेशन मिला, 475 मदरसा अभी पेंडिंग है बिहार सरकार में एफिलियेशन के लिए लेकिन अभी तक उसका एफिलियेशन नहीं मिला है । लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हैं । टोटल मदरसा अभी तक 2443 मदरसा अभी बाकी है एफिलियेशन के लिए तो जो 475 मदरसा है, कम-से-कम उनका एफिलियेशन आप तुरंत दिलवाइए, इसपर पूरा बिहार आक्रोशित है और अगर नहीं कीजियेगा तो आन्दोलन होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।
माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से शिक्षा विभाग को राशि प्रावधानिक करने हेतु आपके माध्यम से सदन से अनुरोध कर रहा हूं । आप परिचित हैं कि बिहार सरकार शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयास कर रही है । हम चाहते हैं कि हमारा मानव संसाधन सुशिक्षित, समर्थ हो ताकि यहां के युवा छात्र-छात्रा राज्य में, देश में एवं देश के बाहर बेहतर भूमिका अदा कर सकें ।

क्रमशः

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री, क्रमशः महोदय, कई माननीय सदस्यों ने आज के बहस में हिस्सा लिया है और तकरीबन 13 सदस्यों ने इसमें हिस्से लिये और सभी 13 माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा, बड़े ही तफसिल से रखा, बहुतों ने प्रशंसा भी की,बहुतों ने मुखालफत भी किया, सुझाव भी दिये और कई लोगों ने सचमुच में बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें कही है और मैं उन सभी सुझावों का एहतराम करता हूॅं, मैंने उसे नोट किया है, मेरे अधिकारी भी यहाॅं बैठे हैं,उन लोगों को भी कहा गया है कि आप सारी बातों को नोट कर लें तो यह सब सुझाव आये और उनका हम एहतराम करते हैं और उसपर हम नियमानुकूल कार्रवाई का वादा करते हैं । माननीय सिद्दिकी साहब ने इसकी शुरुआत करने की इजाजत दी है हमें और कुछ सुझाव दिये भी हैं । महोदय, आप जानते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन की सरकार, काम करने वाली सरकार और यह पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, पूरे बिहार में तो यह है ही, एक ही संदेश लोगों में है कि हमलोग काम करने वाले लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी काम करने वाले हैं और वे इससे प्रेरित है, अल्लामा एकबाल का एक शेर है और वह हमें नसीहत देता है:

"ए ताहिरे लाहोती, उस रिस्क से मौत अच्छी,
जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही ।"

तो हमलोग काम करने वाले लोग हैं............(व्यवधान)

अध्यक्षः वाह । इसका तो अर्थ समझाना पड़ेगा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्रीः महोदय, जानते हैं । परवाज में यानि उड़ान में वैसा भोजन नहीं चाहिए जिससे परवाज में कोताहि आ जाय ।

अध्यक्षः बिल्कुल । यानि इस रिस्क से मौत अच्छी ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः जी । जिस रिस्क से आती हो परवाज तो यह हमारा मानना है ।

अध्यक्षः अब विषय पर आ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्रः महोदय, हमलोग शेरो शायरी सुनने के लिए बैठे हैं,इनको तो शिक्षा पर बोलना चाहिए । आज शिक्षा में जंगल राज हो गया है । इसलिए हमलोग सदन का त्याग करते हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, हमलोग शेरो शायरी सुनने के लिए तो यहाॅं पर नहीं आये हैं, मंत्री जी विषय पर नहीं बोलकर शेरो शायरी कर रहे हैं,इसलिए हमलोग सदन का बर्हिगमन करते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: जरा सुन तो लीजिये । कुछ सच्चाई तो जान लीजिये, कुछ अच्छी बातों को तो सुन कर जाइये । सिद्दिकी साहब कम से कम आप तो सुनकर जाइये । आज जाने की जिद न करो । अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत ही उम्मीद थी.......(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आगे से जब शेर पढ़ियेगा तो थोड़ा हल्का वाला पढ़ियेगा, भारी पढ़ियेगा, तो ये लोग चले जायेंगे ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: हमें बहुत ही उम्मीद थी अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा का महत्व क्या है, इससे सब लोग वाकिफ है और आज बिहार में जिसतरह की शिक्षा व्यवस्था है, उससे पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और हमें उम्मीद थी कि हमारे माननीय विपक्षी दल के सदस्यगण हमारी बातों को सुनेंगे लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया कि लोग बॉयकाट कर गये हैं,तो मैं उनकी अनुपस्थिति में भी अपनी बात कहना चाहता हूँ कि हमलोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किये हैं और खास करके 2005 से जब से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रुप में आये,तो जो बदलाव आया है आज तक, तो इस बदलाव को सब लोग देखकर चकित है और हमारे शिक्षा प्रणाली की चर्चा होती है और लोग प्रशंसा करते हैं । महोदय, गॉधी जी की 150वीं जयंती पर गॉधी विचार समागम हमलोगों ने पटना में आयोजित किया था और देश के चुने हुए गॉधी विचारधारा के लोग यहॉं आये और काफी संख्या में छात्र और छात्राएँ उस दिन उपस्थित थे, गॉधी जी की बातों को हमलोगों ने समागम के माध्यम से लोगों को सुनाने का काम किया और बिहार में शिक्षा का जो स्तर है और जिस क्षेत्र में हमलोग काम कर रहे हैं,उसपर भी हमलोगों ने चर्चा की । महोदय, सब लोग जानते हैं गॉधी कथा वाचन हमारे विद्यालयों में चल रहा है, दो तरह की किताबें हैं, बापू की पाति और एक था मोहन । यह हमलोग विद्यालयों में प्रार्थना के बाद नियमित रुप से इसका वाचन करवाते हैं और कई जगह हमने खुद भी जाकर देखा है, बहुत ही अनुशासित वे में सभी छात्र और छात्राएँ गॉधी कथा वाचन करते हैं और उससे एक अच्छा माहौल बन रहा है बिहार में, खासकरके गॉधी जी जिनको बहुत से लोग भूलते जा रहे थे लेकिन आज फिर बिहार में और बिहार से गॉधी जी फिर से जीवित हो गये हैं और आज समाज इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहा है कि आज देश और राज्य को गॉधी जी के जो विचार है, उसपर चलने की जरुरत है । महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एडुकेशन हमारा सबसे बड़ा विषय है और उसपर हमारा ध्यान ज्यादा है । राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये जा रहे

हैं । राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग–1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को वर्गवार एवं विषयवार अधिज्ञान प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स का निर्धारण किया गया है, वर्ग–5 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र–छात्राओं को दो माह का विशेष शिक्षण देकर पुनः परीक्षा में सम्मिलित करने का अवसर दिया जा रहा है । वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के आधार पर पिछड़ रहे बच्चों ग्रेड–सी,डी एवं ई के उच्चारण शिक्षा का आयोजन की व्यवस्था की गयी है । राज्य का प्रारंभिक विद्यालय का बेस्ट एप के माध्यम से ऑनलाईन अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी है । महोदय, हमारे कतिपय सदस्य माननीय सदस्य शिक्षक नियोजन की बात कर रहे थे । राज्य सरकार द्वारा छठे चरण अन्तर्गत शिक्षकों को नियोजन हेतु कार्रवाई की गयी है । इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक के 90,762 रिक्त पदों पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के 3020 रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है । प्राथमिक शिक्षकों को अंतिम नियुक्ति पत्र 31 मार्च, 2020 एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को अंतिम नियुक्ति पत्र 31 दिसम्बर, 2019 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय आच्छादित किये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में शेष बचे 2950 अनाछादित पंचायतों में अप्रैल, 2020 से वर्ग–9 के संचालन का निर्णय लिया गया है, इनमें से 1412 पंचायतों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु 350 करोड़ की राशि विमुक्त की जा रही है, इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 2020 से सभी 2950 पंचायतों के वर्ग–9 का संचालन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । इसतरह से महोदय नियोजन के क्षेत्र में, हम जानते हैं, हमारी जरुरत है, हम जो उत्क्रमित कर रहे हैं विद्यालयों को, तो नैचुरल है कि हमको शिक्षकों की जरुरत पड़ रही है और हमलोग उस दिशा में इतना आगे बढ़े हैं । उन्नयन बिहार योजना यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और क्वालिटी एडुकेशन के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और सचमुच में इसको हमलोगों ने जा करके देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में यह बात आ गयी कि इसको पूरे बिहार में क्यों नहीं लागू किया जाय, यह बॉका में पहले लागू किया गया था, तो माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से बॉका जिला में उन्नयन बॉका कार्यक्रम चलाया गया और इसके अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के लिए स्मार्ट वर्ग कक्ष स्थापित कर छात्र छात्राओं को पढ़ाया गया ।

क्रमशः

टर्न-18/सत्येन्द्र/27-11-19

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री(क्रमशः): स्मार्ट वर्ग कक्ष में एक टी0वी0 स्क्रीन 55 ईंच लगा रहता है जिसमें विकसित ई-कन्टेंट वी0डी0ओ0 के माध्यम से दिखाकर अध्यापन कार्य किया जाता है जो बच्चों को सीखने में सुविधाजनक रहता है । बांका जिला में इस योजना को अपार सफलता मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी से प्रभावित होकर पूरे बिहार में इसे लागू कर दिया और बिहार के सारे विद्यालयों में ये चल रहा है । यह एक ऐसी प्रणाली विकसित की गयी है जिससे दो फायदे हुए हैं, बच्चे उच्च क्वालिटी की शिक्षा तो प्राप्त कर ही रहे हैं और खासकर के छात्रों की कमी जो दिखती थी विद्यालयों में, लोग नहीं आ पा रहे थे, उनकी संख्या कम थी, इसके बाद विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में छात्र-छात्राएं आ गयीं और अब जो हमारा मकसद था वह पूरा होता नजर आ रहा है । राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उन्नयन बिहार के अन्तर्गत स्मार्ट वर्ग कक्ष की सुविधा सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध करायी जाय, इस हेतु विभाग के द्वारा 90 हजार रु0 प्रति विद्यालय की दर से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट वर्ग कक्ष स्थापित करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है । महोदय, आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से वर्ग 11 एवं 12 के छात्र छात्राओं को भी उन्नयन स्मार्ट कक्ष के द्वारा ई-कन्टेंट से पठन पाठन का निर्णय लिया गया है । इस तरह से हम देखते हैं महोदय कि शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन कैसे आये, इसके लिए हमलोग इस तरह से गंभीर प्रयास कर रहे हैं और इसका प्रतिफल भी अच्छा मिल रहा है । एक बात मैं इसमें जरूर सम्मिलित करना चाहूंगा महोदय कि बिहार विधान सभा का जो चुनाव हो रहा था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी और उस घोषणा पर सबसे ज्यादा तालियां बजती थीं, उसमें इन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चालू करने की बात कही थी और इस पर पूरे भीड़ की तरफ से ताली बजती थी और इस योजना के अन्तर्गत कुल 2460 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और जिससे 88278 छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण का लाभ पहुंचाया गया है । अब गरीब के बच्चे जिनके पिता या अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वे पढ़ना चाहते थे लेकिन अर्थ के अभाव में वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में विफल हो रहे थे तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलायी, इसका अच्छा असर हुआ और गरीबों के बच्चों को

सुविधा मिल गयी । मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना- वित्तीय वर्ष 2019-20 में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2019 में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 10 हजार रू0 की दर से कुल 2 लाख 71 हजार छात्राओं के लिए 271 करोड़ रु0 उनके बैंक खाते में उपलब्ध करा दिया गया है । इस तरह से इस योजना का लाभ भी लोगों को मिलने लगा है और खासकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, इसके माध्यम से काफी लोग प्रोत्साहित हुए हैं । मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 24 हजार 460 छात्राओं को 61 करोड़ रु0 उनके बैंक खाता में उपलब्ध करा दिया गया है । बालिका शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम संचालित है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्नातक बालिका योजना, पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, सेनेटरी नेपकिन योजना आदि साथ ही साईकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना पूर्व से संचालित हैं, फलतः बिहार में बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई और इसको सब लोग स्पष्ट रूप से जमीन पर महसूस कर रहे हैं । आज शिक्षा प्राप्त करने वाले बालिकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो गयी है । आज माध्यमिक स्तर पर बालक-बालिका शिक्षा का अन्तर शून्य है और लगभग दोनों की संख्या सामान हो गयी है। उक्त सभी बालिका से संबंधित योजनाओं का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, कुल प्रजनन में कमी लाना तथा लिंग अनुपात के असमानता को समाप्त करना है और इन सभी उद्देश्यों के प्रति हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है, फलतः पूर्व में जहां मात्र 19 प्रतिशत महिलाएं शिक्षिका थीं वह आज बढ़कर 39 प्रतिशत हो गयी हैं । इस तरह से कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं । खासकर के बालिका छात्राओं की पढ़ाई पर हम ज्यादा गंभीर हैं और उनके लिए चलायी जा रही कई योजनाओं का जिक्र हमने किया है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति- महोदय मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा । समिति ने स्वच्छ कदाचार रहित परीक्षा संचालन में अपना रिकार्ड स्थापित किया है और समिति के द्वारा वर्ष 2019 में मात्र 28 दिनों में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया जो एक रिकार्ड है। महोदय यह इतना अच्छा काम हुआ है कि अन्य राज्यों के लोग, कई राज्यों के लोग अपना प्रतिनिधि भेजकर यह जानने के लिए बिहार में पटना आये कि भई ये करिश्मा कैसे हो गया, इतने कम दिनों में कैसे परीक्षाफल का प्रकाशन हो गया ? महोदय यह

एक बहुत बड़ी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में हुई है और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए दूसरे राज्यों के लोग यहां आ रहे हैं । ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है । समिति के द्वारा परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किये गये कार्य की सराहना देश भर में हो रही है । छतीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से भी शिक्षा विभाग की टीम समिति में पहुंच कर इसकी जानकारी प्राप्त की है । विपक्ष के माननीय सदस्य मदरसा शिक्षा की चर्चा कर रहे थे, चले गये वे लोग और महोदय इन लोगों के नहीं रहने से थोड़ा बात करने का जो सिलसिला रहता है उसका अभाव दिख रहा है इसलिए हम कहेंगे कि अगर कहीं मेरी बात वे सुन रहे हों तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप आइए ताकि हम और बढ़िया बोल सकें । मदरसा शिक्षा में किये गये प्रयास- महोदय, 1127 मदरसों में मार्डन एजुकेशन के लिए प्रति मदरसा तीन पदों पर, विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है । सभी 1127 मदरसों के लिए विज्ञान एवं गणित विषय हेतु 15000 प्रति मदरसा की दर से उपलब्ध कराया गया है । मदरसों में विज्ञान कम्प्यूटर लैब हेतु 1127 मदरसों को कम्प्यूटर प्रिंटर सेट उपलब्ध कराया जा रहा है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आने के पहले बिहार में मदरसा मायने क्या होता था, वह बिल्कुल एक खास चीज की पढ़ाई का केन्द्र बन गया था जिसको दिनी तालिम कहते हैं, वह दिनी तालीम का मरकज बनकर रह गया था लेकिन आज उसको मार्डन तालीम दी जा रही है और सब तरह से उन मदरसों को लैस किया जा रहा है आधुनिकी टेकनोलॉजी से और आज वहां की सूरत बदल गयी है । बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा फकौनिया एवं मौलवी का परीक्षा फार्म ऑनलाइन बढ़ाया गया है एवं इसका परिणाम भी नेट पर जारी कर दिया गया है । मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को जो अप्रशिक्षित थे उनको विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है । अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को पोशाक, साईकिल एवं मध्याह्न भोजन योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है और यह पहले नहीं था, यह साईकिल योजना, पोशाक योजना और मिड डे मिल ये मदरसों में इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था और कोई डिमांड भी नहीं होता था लेकिन यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ये सब कार्यक्रम मदरसों में शुरू हुआ और इसकी सब तरफ तारीफ हो रही है, सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं । बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का 17-2-2019 से शुभारम्भ किया गया है । इसके खुलने से पूर्णिया प्रमंडल के साथ-साथ भागलपुर प्रमंडल के दो जिले भी लाभान्वित हो रहे हैं । अबतक ये रीजनल ऑफिस के नहीं रहने के कारण

सभी जगह के मौलवी लोगों को और वहां के जो संबंधित लोग थे उनको पटना आना पड़ता था और अगर एक दिन में काम नहीं हुआ तो दो दिन रुकना पड़ता था, बहुत दुश्वारी थी लेकिन ये पूर्णिया में रीजनल ऑफिस खुल जाने के बाद से लोगों की दुश्वारियां कम हो रही हैं, आसानी हो गयी है । हमलोग गये थे उसके उद्‌घाटन कार्यक्रम में, काफी उत्साह था लोगों में, बहुत भारी संख्या में लोग, मदरसा के लोग वहां पहुंचे हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे और काफी खुशी लोग जाहिर कर रहे थे तो यह एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है मदरसा के क्षेत्र में । महोदय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के भवन एवं परिसर में विकास- इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन एवं परीक्षा भवन परिसर का विकास मीठापुर, पटना में किया जा रहा है । इसके निर्माण एवं विकास के मद में 82 करोड़ रु0 की स्वीकृति दी गयी है जिसमें से 30 करोड़ रु0 की राशि विमुक्त की जा चुकी है। शिलान्यास हो चुका है, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और ये जो मीठापुर का एरिया है, एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है । उसमें मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के भी भवन की नींव वहां रख दी गयी है जिस पर काम चल रहा है । विश्वविद्यालय की स्थापना- राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के आलावा सात निजी विश्वविद्यालय यथा अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, मधुबनी (क्रमशः)

टर्न-19/आजाद/27.11.2019

...... क्रमशः ......

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : के0के0 विश्वविद्यालय,नालन्दा, डॉ0 सी0वी0 रमण विश्वविद्यालय, वैशाली, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार(सासाराम), अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार एवं माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना की गई है । साथ ही राज्य सरकार द्वारा 3 नये विश्वविद्यालय यथा- पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । ये सारे बड़े-बड़े काम शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में हुआ है और खासकर के उच्च शिक्षा के विकास के लिए ये सारे काम हुए हैं और जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है ।

तकनीकी शिक्षा के लिए आर्यभट्टज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत नैनो सायंस एवं नैनो टेक्नॉलौजी के अध्ययन की व्यवस्था है तथा "School of Journalism and Mass Communication", " Patliputra

School of Economics" and "Centre for River Studies" एवं " Centre for Geographical Studies" के रूप में चार स्वायत शासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की गई है । इस प्रकार बिहार के शैक्षणिक जगत में ठोस और परिणामकारी कार्य करने में हम अग्रसर हैं ।

महोदय, इस तरह की तकनीकी शिक्षा की कल्पना बहुत और अपेक्षा भी लोगों को नहीं थी, लेकिन यह सब मुख्यमंत्री जी की सोच का सारा यह नतीजा है और यह सारा काम इनके नेतृत्व में हो रहा है ।

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना - राज्य सरकार द्वारा अनुमंडल स्तर पर 18 सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित की गयी है । जिमसें 6 महाविद्यालय में इस सत्र से पढ़ाई शुरू कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना- तीव्र गति से शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है जो संचालित भी हो रहा है । महोदय, कॉलेजेज में प्रोफेसर, लेक्चरर की बहाली के लिए बी0पी0एस0सी0 पर निर्भरता थी और उसमें काफी विलंब होता था और लोगों को उसमें काफी प्रतिक्षा करनी पड़ती थी, नियुक्ति प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता था लेकिन अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना देने से नियुक्ति प्रक्रिया सरल हो गई और काफी संख्या में अब यहां पर आसानी से नियुक्ति हो जायेगी तो यह बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना- राज्य सरकार के प्रयास से राज्य में 2 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय यथा - दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया एवं महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की गयी है । तीसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी तेजी से विकास कर रहे हैं ।

NAAC से मान्यता - महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को NAAC से मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रयास किये गये हैं जिसके कारण अभी तक कुल 109 महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को NAAC से मान्यता प्राप्त हो चुकी है ।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में शिक्षा विभाग के लिए स्कीम एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत विभिन्न मदों में द्वितीय अनुपूरक आगणन से कुल 16,10,04,71,000/-(सोलह अरब दस करोड़ चार लाख एकहत्तर हजार)रू0 प्रावधानित करने का प्रस्ताव उपस्थापित है जिसमें से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए

12,59,46,69,000/-(बारह अरब उनसठ करोड़ छियालिस लाख उनहत्तर हजार)रू0 मात्र एवं राज्य स्कीम मद में 3,50,58,02,000/-(तीन अरब पचास करोड़ अन्ठावन लाख दो हजार) रू0 है ।

उपर्युक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत उच्च शिक्षा के वित्त रहित संस्थानों के लिए 500 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के वित्त रहित संस्थानों के लिए 300 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है केन्द्रांश की राशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पूर्व में बजट उपबंध नहीं कराया जा सका । इसलिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में वर्ग-1 से 8 में नामांकित छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन योजना हेतु केन्द्रांश के रूप में 93,92,84,000/- (तिरानबे करोड़ बानवे लाख चौरासी हजार) एवं राज्यांश के रूप में 23,80,84,000/- (तेईस करोड़ अस्सी लाख चौरासी हजार) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

महोदय, साक्षर भारत कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना है । केन्द्रांश की राशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पूर्व में बजट उपबंध नहीं कराया जा सका । इसलिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में साक्षर भारत कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश के रूप में 5,25,00,000/- (पॉच करोड़ पचीस लाख) रू0 एवं राज्यांश के रूप में 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

महोदय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना है । केन्द्रांश की राशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पूर्व में बजट उपबंध नहीं कराया जा सका । इसलिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु केन्द्रांश के रूप में 37,90,00,000/- (सैंतीस करोड़ नब्बे लाख) रू0 एवं राज्यांश के रूप में 34,60,00,000/- (चौतीस करोड़ साठ लाख) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

जल-जीवन-हरियाली योजना हेतु शिक्षा विभाग के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 25,00,00,000/- (पचीस करोड़) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और आज हम सब लोग इस बात से अवगत हैं कि जल-जीवन-हरियाली योजना का अभियान बिहार में बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता के आधार पर परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए इस अभियान को चालू किया है और इसमें शिक्षा विभाग बहुत आगे बढ़-चढ़कर काम कर रहा है ।

बिहार राज्य स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु शिक्षा विभाग के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 4,50,00,000/- (चार करोड़ पचास लाख) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

उन्नयन बिहार योजना हेतु शिक्षा विभाग के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 5,00,00,000/- (पॉंच करोड़) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमिडियट) प्रोत्साहन योजना हेतु शिक्षा विभाग के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 87,57,30,000/- (सतासी करोड़ संतावन लाख तीस हजार) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भू-अर्जन हेतु शिक्षा विभाग के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 29,52,04,000/- (उनतीस करोड़ बावन लाख चार हजार) रू0 की राशि को द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

महोदय, माननीय विपक्ष के सभी सदस्यगण बहुत सारे सुझाव भी दे रहे थे, उनको हमारे जवाब को सुनना चाहिए था लेकिन वे सुन नहीं पाये । हम चाहते थे कि अगर वे रहते तो उन्होंने जो एक-एक विषय उठाया है, लेकिन फिर भी मेरे अधिकारी यहां उपस्थित हैं, मैंने उसको नोट भी करवाया है और मैं अपने अधिकारियों से भी कहूंगा कि जिन बातों का उल्लेख किया गया है हमारे खासकर के विपक्ष के सदस्यों ने, उनको बिन्दुवार देख लेंगे और उस पर समुचित कार्रवाई, जो न्यायोचित कार्रवाई होगी, वह हम करेंगे ।

चूँकि उन लोगों के रहने से सदन में रोचकता आती है, रौनक बनती है, लेकिन नहीं हैं तो फिर हम यह कहना चाहेंगे, खासकर के सिद्दिकी साहेब, हमारे पूर्व के नेता रहे हैं, गुरू रहे हैं, हम उनसे कहना चाहता था कि :-

लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते हो, बस्तियां जलाने में ।

बैठे रहते तो बहुत सारी बातें सुन सकते थे । लेकिन सदन से वे चले गये । अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, ऐसे तो सिद्दिकी साहेब, बैठना चाह रहे थे ...

अध्यक्ष : वो चले गये हैं कोई बात नहीं है, आपने ऐसी बात कही है, वे जहां होंगे, वही लगेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, इनका दिल का दर्द बहुत गहरा है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय,

कुछ तो होता है मोहब्बत में जुनूं का असर,
कुछ लोग तो दिवाना बना देते हैं ।

वो तो बैठना चाह रहे थे, लेकिन उनको जाना पड़ा । अध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरा सदन से अनुरोध है ...

अध्यक्ष : अब आपको ललित यादव जी से अनुरोध करना है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वमा, मंत्री : आखिर में सदन से मेरा अनुरोध है कि अनुपूरक व्यय के इस प्रस्ताव को पारित किया जाए एवं बिहार की शिक्षा के विकास में किये जा रहे प्रयासों के प्रति साकारात्मक समर्थन व्यक्त किया जाए और मैं विपक्ष के माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10 रू0 से घटायी जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :-

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ''शिक्षा विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबंध के अतिरिक्त 16,10,04,71,000/- (सोलह अरब दस करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
मांग स्वीकृत हुई ।

टर्न-20/शंभु/27.11.19

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का मुखबन्ध होगा । प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 के उपबंध के अतिरिक्त :-

मांग संख्या- 01 कृषि विभाग के संबंध में 3,95,92,01,000/- (तीन अरब पंचानवे करोड़ बानवे लाख एक हजार) रूपये,

मांग संख्या- 02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 84,81,95,000/- (चौरासी करोड़ इक्यासी लाख पंचानवे हजार) रूपये,

मांग संख्या- 03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 3,35,64,66,000/- (तीन अरब पैंतीस करोड़ चौंसठ लाख छियासठ हजार) रूपये,

मांग संख्या- 04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 4,54,58,000/- (चार करोड़ चौव्वन लाख अंठावन हजार) रूपये,

मांग संख्या- 07 निगरानी विभाग के संबंध में 19,00,000/- (उन्नीस लाख) रूपये,

मांग संख्या- 09 सहकारिता विभाग के संबंध में 37,27,11,000/- (सैंतीस करोड़ सत्ताईस लाख ग्यारह हजार) रूपये,

मांग संख्या- 10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 12,00,000/- (बारह लाख) रूपये,

मांग संख्या- 11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 2,58,45,000/- (दो करोड़ अंठावन लाख पैंतालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या- 12 वित्त विभाग के संबंध में 1,05,55,000/- (एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार) रूपये,

मांग संख्या- 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 3,50,90,00,000/- (तीन अरब पचास करोड़ नब्बे लाख) रूपये,

मांग संख्या- 17 वाणिज्य-कर विभाग के संबंध में 51,41,000/- (इक्वायन लाख इकतालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या- 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 89,00,000/- (नवासी लाख) रूपये,

मांग संख्या- 19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 4,11,69,69,000/- (चार अरब ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख उनहत्तर हजार) रूपये,

मांग संख्या- 20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 11,34,87,64,000/- (ग्यारह अरब चौंतीस करोड़ सतासी लाख चौंसठ हजार) रूपये,

मांग संख्या- 22 गृह विभाग के संबंध में 4,86,54,90,000/- (चार अरब छियासी करोड़ चौव्वन लाख नब्बे हजार) रूपये,

मांग संख्या- 23 उद्योग विभाग के संबंध में 3,55,40,000/- (तीन करोड़ पचपन लाख चालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या- 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 50,84,50,000/- (पचास करोड़ चौरासी लाख पचास हजार) रूपये,

मांग संख्या- 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 35,37,47,000/- (पैंतीस करोड़ सैंतीस लाख सैंतालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या- 27 विधि विभाग के संबंध में 3,25,00,000/- (तीन करोड़ पच्चीस लाख) रूपये,

मांग संख्या- 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 43,25,00,000/-(तैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये,

मांग संख्या- 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार) रूपये,

मांग संख्या- 32 विधान मंडल के संबंध में 10,85,00,000/- (दस करोड़ पचासी लाख) रूपये,

मांग संख्या- 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 25,42,65,000/- (पच्चीस करोड़ बेयालीस लाख पैंसठ हजार) रूपये,

मांग संख्या– 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 5,38,43,000/– (पाँच करोड़ अड़तीस लाख तैंतालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या– 38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 28,44,10,000/– (अट्ठाइस करोड़ चौव्वालीस लाख दस हजार) रूपये,

मांग संख्या– 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 19,17,97,01,000/– (उन्नीस अरब सत्रह करोड़ संतानवे लाख एक हजार) रूपये,

मांग संख्या– 40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 25,35,45,000/– (पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या– 41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 4,50,00,00,000/– (चार अरब पचास करोड़) रूपये,

मांग संख्या– 42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 6,47,25,37,000/–(छः अरब सैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार) रूपये,

मांग संख्या– 43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 76,70,52,000/– (छिहत्तर करोड़ सत्तर लाख बावन हजार) रूपये,

मांग संख्या– 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 28,94,40,000/– (अट्ठाइस करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या– 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 49,00,000/– (उनचास लाख) रूपये,

मांग संख्या– 47 परिवहन विभाग के संबंध में 10,00,00,000/– (दस करोड़) रूपये,

मांग संख्या– 48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 9,71,66,53,000/–(नौ अरब इकहत्तर करोड़ छियासठ लाख तिरपन हजार) रूपये,

मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 5,34,22,00,000/– (पाँच अरब चौंतीस करोड़ बाइस लाख) रूपये,

मांग संख्या– 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 8,01,62,00,000/–(आठ अरब एक करोड़ बासठ लाख) रूपये,

मांग संख्या– 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 11,63,17,07,000/–(ग्यारह अरब तिरसठ करोड़ सत्रह लाख सात हजार) रूपये,

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

विधाय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य ।

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019'' प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-21/ज्योति/27-11-2019

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय अनुपूरक व्यय विवरणी 22 नवम्बर 2019 को इस सदन में उपस्थापित किया गया था । इस द्वितीय व्यय अनुपूरक व्यय विवरणी में 12457 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जिसमें स्कीम वाईज पहले प्लान के नाम से जाना जाता था जिसमें 5962 करोड़ रुपया और नौन प्लान यानी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 6480 करोड़ रुपया है । अध्यक्ष महोदय,

मैं केवल कुछ प्रमुख जो प्रावधान किया गया है उसका उल्लेख करना चाहूंगा । इस सेकेन्ड सप्लीमेंट्री में जो सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है उसमें 1688 करोड़ रुपया यह जल जीवन, हरियाली मीशन के लिए प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, सदन को मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जल जीवन हरियाली अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है उसकी पृष्ठ भूमि में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो अभियान है इसमें 11 तरह के काम मुख्य रुप से किए जा रहे हैं और मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप सभी लोगों के और आम नागरिकों के सहयोग की इसमें आवश्यकता होगी । इसमें एक काम तो यह कि जितनी जल संचयन संरचनाएं हैं यथा तालाब, पोखर, आहर, पईन ये जितने भी तालाब, पोखर आहर, पईन है तीन काम किया जाता है । पहला तो इनको चिन्हित किया जाना फिर इनका जीर्णोद्धार किया जाना और अतिक्रमण मुक्त किया जाना । तो ये जो चिन्हित अतिक्रमण मुक्त और जीर्णोद्धार तो मैं सदन को बतना चाहूंगा कि कल तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार में 1 लाख 32 हजार तालाब जो हैं ये चिन्हित किए गए हैं और इनका निरीक्षण किया गया, इंसपेक्शन किया गया तो 90,513 तालाबों का निरीक्षण अभी तक पूरा हो चुका है और 11,948 तालाब पाए गए जो अतिक्रमित हैं तब उसको अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी इसलिए तो इसमें एक काम तो है कि तालाब, पोखर, आहर, पईन को चिन्हत करना, जीर्णोद्धार अतिक्रमण मुक्त फिर दूसरा है कि जितने सार्वजनिक कुएं हैं उनको चिन्हित करना और उसका जीर्णोद्धार करना और 3 लाख 1 हजार 316 कुएं हैं जिसमें अभी तक जो इंसपेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया, उसमें 1 लाख 31 हजार 742 कुओं का निरीक्षण पूरा हो चुका है और अध्यक्ष महोदय, यह जो कुओं का जीर्णोद्धार करना है यह 15 अगस्त, 2021 तक इसके जीर्णोद्धार के लिए समय निर्धारित किया गया है । उसी प्रकार जितने सार्वजनिक कुएं हैं, चापाकल और नलकूप हैं उसके किनारे सोखता और रिचार्ज की संरचना का निर्माण करना है । चौथा है छोटी-छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम और अन्य जल संरचनाओं का निर्माण किया जाना है । नये जल स्रोतो का भी सृजन किया जाना है । जितने सरकारी भवन हैं उन सारे सरकारी भवनों में वर्षा के जल का संचय करना और उसको जमीन के नीचे पहुंचाना जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं ये सभी और पहले जितने स्कूल हैं, अस्पताल हैं उनमें यह काम किया जायेगा और फिर उसके बाद जो निजी भवन हैं उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा

। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जायेगा । सदन को ज्ञात है कि ग्रामीण विकास विभाग और फौरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर डेढ़ करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा था और उसमें सवा करोड़ वृक्ष हम लगा चुके हैं और इस जाड़े में पौपुलर और प्लांट लगाये जायेंगे और अगले साल हमलोग एक दिन में दो करोड़, 51 लाख पौधे जो हैं एक दिन में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ सिंचाई पर कम निर्भरता वाली वैकल्पिक फसलों, ड्रीप एरीगेशन, जैविक खेती एवं अन्य तकनीकों के उपयोग से किसानों को प्रेरित करना और इस पूरे काम के लिए अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 24,524 करोड़ रुपया अगले तीन वर्षों के अंदर व्यय किया जाना है और इस सेकेंड सप्लीमेंट्री में 1688 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है 700 करोड़ रुपया लघु जल संसाधन को सार्वजनिक जल संचयन तालाब, पोखर, आहर एवं पईनों का जीर्णोद्धार यह लघु जल संसाधन के माध्यम से 700 करोड़ और चेक डैम वगैरह के लिए 100 करोड़ यानी 800 करोड़ रुपया केवल लघु जल संसाधन विभाग के लिए प्रावधान किया गया है । जल संसाधन विभाग के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है ताकि जो नये जल स्रोतो का सृजन एवं बचे हुए नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल को ले जाना एवं फिर 219 करोड़ रुपया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए प्रावधान किया गया है ताकि नर्सरी का निर्माण करना, नर्सरी में पौधे तैयार करना ताकि अगले वर्ष हम बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य कर सकें । तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए विस्तार से जिक्र किया है कि जल जीवन हरियाली अभियान और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि जल बचेगा और हरियाली बचेगी तब ही जीवन बचेगा इसलिए जीवन को बीच में रखा गया है इसलिए जो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है उसका मुकाबला करने में मुझे लगता है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिए इतनी बड़ी योजना बनाकर, केवल योजना नहीं बनायी बल्कि इसको लागू करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार एक बहुत बड़ी राशि का प्रावधान हमलोगों ने 1917 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन विभाग के लिए किया है । मैं सदन को बताना चाहूंगा और आपको याद होगा कि जब 2018-19 में यानी पिछले वित्तीय वर्ष में और जब सूखा पड़ा था तो राज्य के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोाषित किया गया था और उस समय 14 लाख लोगों को 919 करोड़ रुपया हम लोगों ने डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में भेजने काम किया था और इस साल 2019-20 में जुलाई में जब बाढ़

आयी तो दसवें दिन लोगों के खाते में पैसा जाना प्रारम्भ हो गया और जुलाई,2019 के बाढ़ में 25 लाख 80 हजार परिवारों के खाते में 6-6 हजार रूपया प्रति परिवार 1547 करोड़ रूपया हमलोग अपने बजट से निकाल कर 25 लाख 80 हजार परिवारों के खाते में देने का काम किया है । फिर दोबारा बाढ़ आ गयी सितंबर महीने में, फिर हमलोगों ने 6-6 हजार रूपया 6 लाख 23 हजार परिवारों के खाते में कुल मिलाकर 373 करोड़ 92 लाख रूपया भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जुलाई में जो 2019 की जो बाढ़ आई, यह तो जी0आर0 दिया गया पीड़ितों के खाते में, लेकिन जो फसल की क्षति हुई तो 2019 की जुलाई की बाढ़ में 1 लाख 75 हजार हेक्टेअर भूमि में फसलों की क्षति हुई और उसके लिये 236 करोड़ रूपया हमलोगों ने प्रावधान किया है, लोगों ने आवेदन देना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द उन आवेदनों का निष्पादन करके ये राशि उनके खाते में दी जायेगी । फिर सितंबर में जो बाढ़ आई, उसमें भी 2 लाख 20 हजार हेक्टेअर जमीन, जो कृषियोग्य भूमि है, उसमें फसल मारी गयी, उसके लिये भी 271 करोड़ रूपये का हमलोगों ने सेकेंड सप्लमेंटरी के माध्यम से उसका प्रावधान किया है । महोदय, हमलोग तो सोच भी नहीं सकते कि जब एक ओर बाढ और दूसरी ओर कुछ ऐसे इलाके थे, जहां कम वर्षा हुई और वैसे इलाके में 3 लाख 90 हजार हेक्टेअर जहां अल्प वर्षापात में धान की रोपनी और बोआई 70 परसेंट से कम आच्छादन हुआ था, सरकार ने तय किया कि उनके भी खाते में हम 3-3 हजार रूपया हम तत्काल सहायता के रूप में देंगे और अभी तक 9 लाख 1 हजार परिवारों को 207 करोड़ रूपया भेजा जा चुका है । महोदय, बिहार गरीब राज्य है। बहुत सीमित संसाधन है, उसके बावजूद, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि अभी तक जिसमें मैंने यह नहीं जोड़ा है सूखा वाला 919 करोड़ रूपया, केवल 2019-20 में जो 2029 में जुलाई की बाढ़, सितंबर की बाढ़, फसल क्षति जुलाई में फिर फसल क्षति सितंबर में फिर अल्प वर्षापात का तात्कालिक सहायता, सदन को बताना चाहूंगा कि 2 हजार 699 करोड़ रूपया यह बिहार सरकार ने अपने खजाने से खर्च करने का काम किया । इसमें कुछ राशि केन्द्र से मिली लेकिन अधिकांश राशि हमको अपने बजट से ही व्यवस्था करनी होगी । महोदय, अगर सूखा नहीं पड़ता, बाढ़ नहीं आती तो इसी राशि का इस्तेमाल हम पुल-पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य कार्यों में कर सकते थे । लेकिन बार-बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सरकारी खजाने पर सबसे पहला अधिकार इस राज्य के ये आपदा पीड़ितों का है, बाढ़ पीड़ितों का है सूखा पीड़ितों का है और इसीलिये इतनी बड़ी राशि जो खाते में

पहुंच चुकी है । इसलिए 2 हजार 699 करोड़ रूपये हमलोगों ने केवल आपदाग्रस्त लोगों के खाते में पहुंचाने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, इस सेकेंड सप्लीमेंटरी में एक और बड़ा प्रावधान किया गया है, वह है स्वास्थ्य क्षेत्र में । स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल मिलाकर 1134करोड़ रूपये का प्रावधान सेकेंड सप्लीमेंटरी के माध्यम से किया गया है जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये 647 करोड़ रूपया, चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण हेतु 143 करोड़ रूपया, आपको माालूम है कि 11 नये चिकित्सा महाविद्यालय बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है । अनेक चिकित्सा महाविद्यालय बनने की प्रक्रिया में है । कुछ का शिलान्यास हो गया । कुछ लगभग पूरा हो गया । कुछ आगे बननेवाले हैं और इसीलिये बक्सर, झंझारपुर, सीतामढ़ी और जमुई इसके लिये हमलोगों ने और चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये 143 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है ।

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिये 78 करोड़ 50 लाख वहां पर मशीनों के क्रय के लिये, स्टेट कैंसर संस्थान के लिये 52 करोड 90 लाख की लागत से और स्टेट कैंसर संस्थान, आई.जी.आई.एम.एस.,पटना में स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट पटना में स्थापित किया जा रहा है । भागलपुर और दरभंगा में टर्सरी कैंसर केयर संस्थान यानी अब कैंसर के मरीजों को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसके लिये भी इस सेकेंड सप्लीमेंटरी में 52 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 43 करोड़ 85 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । तो कुल 1134 करोड़ रूपये का प्रावधान स्वास्थ्य क्षेत्र में सेकेंड सप्लीमेंटरी के माध्यम से किया गया ।

अध्यक्ष महादय, बिहार के जो गरीब हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं या जो वृद्ध हैं, उनके लिये भी हम एक बहुत बड़ी राशि सदन को बताना चाहूंगा कि राज्य के वृद्ध, विधवा, निशक्त लोगों को 2017-18 में 59 लाख 73 हजार लोगों को 2 हजार 231 करोड़ रूपया भुगतान किया गया है और 2018-19 में 63 लाख 43 हजार लोगों को 2,980 करोड़ रूपया सहायता के रूप में भुगतान किया गया और 2019-20 में, अभी नवंबर महीना चल रहा है, अभी तक 64 लाख 22 हजार लोगों को सितंबर तक का पैसा उनके खाते में भेज दिया गया है और दिसंबर महीने में अक्टूबर, नवंबर का पैसा भी उनके खाते में भेज दिया गया है ।

मित्रों, आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार में प्रारंभ की गयी थी, यह सभी वृद्धजनों को हम पेंशन देने का काम करेंगे । तो भारत सरकार की योजना के अतिरिक्त चूंकि भारत सरकार की योजना में इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं दे सकते हैं । अपने राज्य में वृद्धजनों की बहुत बड़ी संख्या है । मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सभी वृद्धजनों को हम पेंशन देंगे और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि अपने-अपने पंचायत में सर्वेक्षण करके एक भी वृद्धजन छूटें नहीं,

क्रमश:

टर्न : 22/कृष्ण/27.11.2019

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री (क्रमश :) सभी लोगों का आवेदन डलवाईये ताकि कोई वृद्ध वंचित न रहे । अध्यक्ष महोदय, 24 नवंबर तक 16 लाख 12 हजार वृद्ध लोगों ने आवेदन दिया है । सितंबर माह तक 5 लाख 28 हजार आवेदकों का भी भुगतान किया जा चुका है । शेष 2 लाख 46 हजार दिसंबर में पूरा हो जायेगा और बाकी आवेदनों की जांच की प्रक्रिया चल रही हैं और इस बजट में 835 करोड़ रूपये का सेकेंड सप्लीमेंटरी के माध्यम से प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, वित्त रहित शिक्षा नीति को हमारी सरकार ने समाप्त किया और वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुये स्थापना की प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इन्टर महाविद्यालय तथा एफिलियेटेड डिग्री कॉलेजों में फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन के आधार पर अनुदान की राशि दी जाती है तो जो इन्टर स्कूल और हाई स्कूल हैं, उनके शैक्षणिक सत्र 2014 से 2016 के लिये सेकेंड सप्लीमेंटी में 300 करोड़ की व्यवस्था की गयी है और डिग्री महाविद्यालयों के लिये सत्र 2009 से 2012 और 2014 से 2017 तक यानी कुल 6 सत्रों के लिये 500 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा । राजगीर के अंदर खेल संरचना के लिये जो स्टेडियम बन रहा है, उसके लिये 120 करोड़ रूपये, पटना मेट्रो के लिये 100 करोड़ रूपये, मुख्य मंत्री कन्या उत्थान के लिये 87 करोड़ रूपये उसी प्रकार नॉन प्लान यानी स्थापना प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत 1 हजार 63 करोड़ रूपये जो राज्य सरकार पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को देती है, उसके लिये 1 हजार 63 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । पथ निर्माण विभाग की सड़कों के मेन्टीनेंस के लिये 450 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । बिहार

राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के बकाये वेतन के लिये 126 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 12,457 करोड़ 61 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । मैं सदन से आग्रह करूंगा कि द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या-4)विधेयक,2019 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । सदन से अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-4)विधेयक,2019 को अपनी सहमति व्यक्त करते हुये ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार विनियोग (संख्या-4)विधेयक, 2019 स्वीकृत हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-4)विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

निवेदन

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 नवंबर, 2019 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 43 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जायं ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक 28 नवंबर,2019 के 11 बजे पूर्वा0 तक के लिये स्थगित की जाती है ।